:: राजस्थान की सड़कों के लिए 5 हजार करोड़ से अधिक स्वीकृत ::

आर. एन.आई नं. 71880/99

जयपुर-उदयपुर से प्रकाशित

मूल्य : बीस रूपये
मार्च 2025

हमारी ज़िन्दगी

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील से राजस्थान में पानी एवं पेयजल आपूर्ति के बारे में वार्तालाप करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा तथा जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने श्री पाटील को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं।

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से राजस्थान के लिए 5 हजार करोड़ रुपए के सड़क निर्माण की स्वीकृति पर धन्यवाद देते हुए राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी।

पिंकसिटी प्रेसक्लब में तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित मुकेश मीणा, वहीं पांचवी बार निर्वाचित महासचिव मुकेश चौधरी, उपाध्यक्ष के दो पदों पर डॉ. मोनिका शर्मा और परमेश्वर प्रसाद शर्मा निर्वाचित घोषित हुए है। कोषाध्यक्ष पद पर विकास शर्मा चुने गए। वहीं कार्यकारिणी में मणिमाला शर्मा, ओमवीर भार्गव, दिनेश कुमार सैनी, दीपक सैनी, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, अनिता शर्मा, निखलेश शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, उमंग माथुर, विकास आर्य निर्वाचित घोषित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण में राजस्थान भी अग्रणी

श्रीमती अल्का व्यास
ईई पीडब्ल्यूडी, नगर खंड, अलवर

श्रीमती हिमांशी जीनगर
ईई, विद्युत पीडब्ल्यूडी, जोधपुर

प्रेरणा माहेश्वरी
ईई पीडब्ल्यूडी नगर खंड, जोधपुर

जागृति बंसल
अभियंता पीडब्ल्यूडी, चित्तौड़गढ़

:: जलदाय विभाग में अब अवैध कनेक्शन बर्दाश्त नहीं ::

इन दिनों जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी गर्मियों में जनता को पेयजल सुलभ कराने के लिए विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दे रहे हैं

राजस्थान सरकार के अनुभवी एवं प्रतिभाशाली अधिकारी

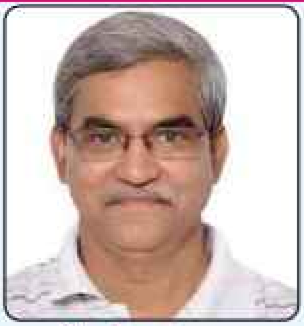

कौशलेन्द्र भारद्वाज
एसीई पीडब्ल्यूडी अजमेर रीजन

मंगनी राम रैगर
अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, राजसमंद

श्री महावर
डीजीएम विद्युत आरएसआरडीसी, जयपुर

एस.पी. बोहरा
पीडी विद्युत आरएसआरडीसी, जोधपुर

मोहनलाल मीणा सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित

जयपुर। सहायक कर्मचारी संघ के हाल ही में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर मोहनलाल मीणा निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने उनको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी।

वर्ष 25, अंक-3

सम्पूर्ण समाचार पत्रिका

हमारी ज़िन्दगी

आर. एन. आई. नं. 71880/99 जयपुर, मार्च 2025 मूल्य : बीस रूपये

पोस्टल लाइसेंस नं. JaipurCity/070/2013-15

समूह सम्पादक

राकेश माथुर
"प्रसून"
9314028732

प्रधान सम्पादक

सौरभ माथुर
8560990000

विशेष संवाददाता

जयपुर : सुभाष चंद्र मित्रुका
इन्दौर : अशोक रघुवंशी
भोपाल : संजय पटेल
जैसलमेर : चन्द्रभान सिंह सोलंकी
बीकानेर : रामलाल लावा
चूरू : कपिल शर्मा
कला व साहित्य : संश्रुती साहू

ब्यूरो प्रमुख

दिल्ली : अनुभव माथुर
मुम्बई : प्रवीण वल्लभ

कार्यालय

जयपुर
ज़िन्दगी हाउस 111/172
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर
जयपुर -302020
फोन : 0141-4039799

इन्दौर
102, WA12, स्कीम 94
विजय नगर इन्दौर-452010
फोन : 0731-4003872

न्यूज पोर्टल

www.bhartianews.com
www.hamarizindagimagazine.com

hamarizindagijaipur@gmail.com
editor@hamarizindagimagazine.com
facebook.com/hamarizindagimagazine
twitter.com/bhartianews

न्यूज डेस्क व्हाट्सऐप

6232734770 | 85680990000

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक राकेश प्रसून के लिए प्रसून प्रिन्टर्स, जयपुर में मुद्रित तथा 111/172, अग्रवाल फार्म, जयपुर से प्रकाशित। संपादक राकेश कुमार माथुर।

अनुक्रमणिका

(1)	समाज में बुराइयां व अपूर्णता समाप्त हो	04
(2)	1949 में एक तिहाई राजस्थान में नहीं थी सड़कें, अब प्रगति की स्पीड	05
(3)	जयपुर-किशनगढ़ हाइवे के अब सभी दस ब्लैक स्पॉट्स समाप्त	06
(4)	आरएसआरडीसी के पदाधिकारियों के विवरण व फोन नम्बर	07
(5)	दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाना प्राथमिकता : एसई भूरी सिंह	08
(6)	मुहाना मंडी जंक्शन पर 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा	09
(7)	पीडब्ल्यूडी ने डीपीआर बनाई, एनएचएआई नई डीपीआर बनाएगा	10
(8)	जयपुर-दिल्ली हाइवे : परिवहन मंत्री ने उजागर किया टोल वसूली का सच	11
(9)	राजेन्द्र गुर्जर, अतुल कुमार व राजेश व्यास को निजी सचिव के पद पर पदोन्नति	12
(10)	मॉडल कोई भी हो जनता से वसूलेंगे टोल	13-14
(11)	सरिस्का में जल्द खुलेंगे दो नई सफारी जोन	15
(12)	बे-मिसाल बेनिमाल	16
(13)	करते हैं कमाल डूंगरराम मेघवाल	17
(14)	पर्यटकों को खूब लुभा रहे रिनोवेटेड कमरे	18
(15)	छह माह पहले जिस प्रवर समिति को भेजा, उसे ही वापस लौटाया	19
(16)	जयदन में गूंजा जेजेएम घोटाला, पड़ोसी राज्यों से हक का पानी लेने की उठी मांग	20
(17)	पंजाब से नदियों का कम मिल रहा पानी, वो भी दूषित, फैल रही बीमारी	21
(18)	ट्रांसफर के 2 माह बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे इंजीनियर्स	22
(19)	पश्चिमी राजस्थान में पानी की बढ़ी उम्मीद, गुजरात सीएम को लिखा पत्र	23
(20)	10,000 गांव-ढाणी और 70 शहर प्यासे 691 बांधों में बचा 49 प्रतिशत पानी	24
(21)	69 करोड़ का जगतपुरा फेज-II व 82 करोड़ का	25
(22)	50 हजार मीटर लोहे की पाइप लाइन घोटाला पीएचईडी ने पकड़ा	26
(23)	छोड़नी होगी प्यास लगने पर कुआं खोदने की प्रवृत्ति	27
(24)	फर्जी भुगतान की पड़ताल कमेटियों ने किया तमाशा, रोकी जांच रिपोर्ट	28
(25)	एसीबी की गोपनीय जानकारी में एसई की 40 से अधिक सम्पत्ति मिली तो	29
(26)	एसीएस गुप्ता व सावंत को 3-3 माह का सिविल कारावास	30

छपते-छपते

▸ एईएन से एक्सईएन की डीपीसी 26 मार्च को हो गई है जिसमें लगभग 198 अधिशाषी अभियंता बनेंगे। महत्वपूर्ण पदों के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी हैं। ▸ उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी एक आवश्यक बैठक मंगलवार 1 अप्रेल को निर्माण भवन में लेंगी जिसमें प्रदेश की सड़कों एवं अन्य परियोजनाओं पर चर्चा होगी।

-आवश्यकता है-

हमारी ज़िन्दगी मैगजीन, न्यूज पेपर एवं भारतीय न्यूज (डिजीटल) के जयपुर एवं इन्दौर कार्यालयों हेतु प्रत्येक जिले एवं तहसील स्तर पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन प्रतिनिधियों तथा न्यूज पेपर एजेन्टों की। इस कार्य हेतु रूपये 500/- अमानत राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। पूर्ण विवरण फोटो सहित जयपुर अथवा इन्दौर कार्यालयों पर आवेदन करें। विशेष जानकारी मोबाइल नं. 9314028732 पर प्राप्त करें।

"हमारी ज़िन्दगी" मैगजीन में

विज्ञापन भुगतान, वार्षिक चन्दा अथवा किसी भी प्रकार का डोनेशन इत्यादि देने के लिए निम्न बैंक खाता नम्बर का उपयोग करें

एसबीआई खाता नं.- 61228617307, आईएफएससी कोड: SBIN0032160

प्रधान संपादक

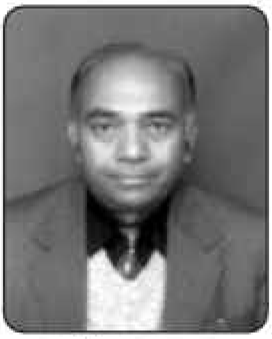

राकेश प्रसून

सौरभ माथुर
(सम्पादक)
हमारी ज़िन्दगी, भारतीय न्यूज
(राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़)

समाज में बुराइयां व अपूर्णता समाप्त हो

हिन्दू नववर्ष के शुभागमन पर देश के प्रमुख संतों ने हिन्दू समाज में जागृति और एकता का आह्वान किया। विगत कुछ वर्षों के दौरान पूरे देश में हिन्दू धर्म के पुनर्जागरण की भावना देशवासियों में मुखर हुई है। इस विषय पर ना केवल देश के साधु-संत समाज ने अपितु समाज के लगभग सभी वर्गों ने अपने-अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए हैं। इन सन्देशों में प्रमुख बात यह रही है कि हिन्दू समाज में कभी व्याप्त रही जाति-पांति की बुराई ने इसका बहुत नुकसान किया है। विगत लगभग एक दशक से समूचे देश के राष्ट्रवादी समूहों में यह बात तेजी से और व्यापक रूप से पनप रही है कि हिन्दू समाज पर जाति के आधार पर बंटे रहने के कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। कोई इसे माने या ना माने सच यही है कि सामान्य तौर पर कई दशकों से भारतीय समाज ने मुखरतौर पर जाति-पांति को बढ़ावा नहीं दिया। सच कहें तो अब यह प्रथा केवल अकादमिक बहस या विमर्श की ही रह गई है। जैसे-जैसे कोई भी समाज प्रगति करता है-वह कई तरह के दुराग्रहों से मुक्त होता रहता है। वह चाहे जाति प्रथा, क्षेत्रियतावाद, भाषावाद जैसी बुराइयां हों या लड़कियों के साथ भेदभाव करना या धर्म सम्बन्धी रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर विश्वास करना इसके प्रमाण हैं। सौभाग्य से अब आमतौर पर हमें अपने सामाजिक व्यवहार में कोई भी ऐसी बुराई दिखाई देती नहीं है। एक उदाहरण लें। हम सबने विगत कुछ दशकों के दौरान रेलों में सफर किया है। आज भले ही जगह-जगह प्लास्टिक की थैलियों में पानी बिक रहा हो, लेकिन सच यही है कि हमने लम्बे अरसे तक रेलवे स्टेशनों सहित विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक प्याऊ से पानी पिया है। हम सबके दिमाग में यह कभी नहीं आया कि उस प्याऊ पर जो व्यक्ति हमें पानी पिलाता था, वह किसी जाति का है? आज के भारतीय समाज में लगभग हर दूसरे-तीसरे घरों में समर्थ लोगों ने कामवाली बाई, ड्राईवर या कार्यालय सहायक / चपरासी आदि-आदि रखे हुए हैं। अब भारतीय समाज की संरचना में मूलभूत बदलाव / सुधार इतना व्यापक और तीव्र गति से हुआ है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार फैसला लेते हैं- किसी की जाति, धर्म या क्षेत्रियता / भाषाई आधार पर नहीं। हमारे छोटी-बड़ी उम्र के बच्चे-बच्चियां भी स्कूल / कॉलेजों में जाने लगे हैं। हम में से किसी को नहीं पता कि उनके सहपाठी / मित्र -जिनके साथ वे समय-समय पर खाना-पीना करते हैं, सिनेमा देखते हैं, एक-दूसरे के परिवार में आते-जाते हैं-कभी उनकी जाति या धर्म पूछा गया? क्या इन आधारों पर वे संबंध बनाने या तोड़ने की सोचते हैं? जिन घरों में कभी अंतरजातीय विवाह नहीं होता था, वहां अब इस धारणा की चिंदी-चिंदी हो चुकी है। आजकल के बच्चे अपनी मित्रता या परिचय में जाति जैसी रूढ़ीवादी प्रथा को कोई स्थान नहीं दे रहे। आज के युवाओं में मित्रता या संबंधों को स्थापित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले में गुण क्या हैं, उसकी रूचियां और स्वभाव हमारे बच्चों के साथ कितने मिलते हैं। वे समय के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह आगे बढ़कर एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं या एक-दूसरे के जीवन को सुधार सकते हैं। बात चल रही थी हिन्दू समाज में जागृति और एकता की। मानकर चलिये कि भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजाराम मोहन राय ने लगभग साढे तीन सौ वर्ष पूर्व ही भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी थी। समाज सुधारकों में उन जैसे दर्जनों महान व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से देखा जाता था। भारत में छुआछूत को दूर करने, बालविवाह प्रथा को बंद करने, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने, घर की बेटियों को बेटों की तुलना में दोयम दर्जे का मानने और बताने जैसे अनेक दुराग्रह समय-समय पर ऐसे ही महान नायकों के प्रयासों से समाप्त होते रहे हैं। विश्वभर के महान चिंतकों ने बहुत पहले कह दिया था कि किसी भी समाज में जैसे-जैसे शिक्षा का विस्तार होगा- वहां ऐसी बुराइयां, कुप्रथाएं धीरे-धीरे समाप्त होती जाएंगी। यह सही है कि पूरी तरह से शायद कोई भी बुराई हमारे मन-मस्तिष्क से पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन हम जिन परिजनों या मित्रों के सम्पर्क में निरंतर रहते हैं, उनके बीच अपनी छवि को बिगड़ने से रोकने के लिए भी हम ऐसे सुधारों को आत्मसात करते रहते हैं। मौजूदा संदर्भ में हमने अपने समाज की अनेक बुराइयों को त्यागा है, लेकिन हमारे ग्रामीण, आदिवासी व दूर-दराज के इलाकों में अभी भी यह बुराइयां व्याप्त होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, फिर भी यह जरूर कहेंगे कि सैंकड़ों वर्षों से जो बुराइयां समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं, उनका पूर्णतया शमन करना आसान नहीं होता। अब चूंकि शिक्षा आम भारतीय के लिए आसानी से उपलब्ध है, ज्ञान और जानकारी को प्राप्त करना बहुत सरल, सहज और सस्ता हो गया है। सरकार और सामाजिक संगठन इस दिशा में बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हम सब अपनी-अपनी तरफ से अपने समाज में जागृति और एकता लाने का प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम अपने इन उद्देश्यों में सफल ना हो पाएं।

1949 में एक तिहाई राजस्थान में नहीं थी सड़कें, अब प्रगति की स्पीड

26 जिलों में से 15 जिलों में सड़कें नहीं थी, आज 3.17 लाख किमी सड़कों का बिछा जाल

राज्य में सड़कों का घनत्व 92.66 किमी प्रति 100 वर्ग किमी

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह तुलनात्मक दृष्टि से कम आबादी का राज्य है। राज्य में 1949 में 13,553 कि.मी. सड़कें थी, जिनमें 794 किमी डामर और 2037 किमी सड़कें मैटल की बनी हुई थी, लेकिन आज राज्य में सड़कों की लंबाई 3,17,121 किमी हो गई हैं अर्थात् हर तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ हैं।

सड़कों का घनत्व 92.66 किमी प्रति 100 वर्ग किमी

राज्य मे 31 मार्च 2024 तक कुल सड़कों की लंबाई 317121 किमी हो गई है, जिसमे से 2,56,148 किमी डामर, 8702 किमी मैटल, 40,736 किमी ग्रेवल सड़के एवं 11,535 किमी मौसम सड़के है। राज्य मे सड़कों का घनत्व 92.66 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है, जबकि राष्ट्रीय घनत्व मोर्थ नई दिल्ली की बेसिक रोड स्टेटिक्स ऑफ इंडिया 2018-19 के अनुसार 165.24 वर्ग किमी हैं।

41 जिलों में से 15 जिले सड़कों से जुड़े थे

राज्य में 1949 में सड़कों का घनत्व मात्र 3.96 किमी प्रति 100 वर्ग किमी था तथा एक लाख जनसंख्या पर मात्र 85.24 किमी सड़के थी। यहा तक कि कई जिला मुख्यालय भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। राज्य के वर्तमान 41 जिलों में से केवल 15 जिले, 100 उपखण्डो में से 54 उपखंड व 339 तहसील मुख्यालयों में से 102 तहसील मुख्यालय ही सड़कों से जुड़े हुए थे।

सड़कों के लिए 20 साल से पेट्रोल-डीजल पर वसूल रहे सेस

राज्य में सड़क विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राजस्थान विधानसभा ने वर्ष 2004 में अधिनियम संख्या 13 के तहत राजस्थान सड़क विकास अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत राज्य में पेट्रोल-डीजल पर सेस अधिरोपित किया गया। वर्तमान में 15 जनवरी 2016 से पेट्रोल पर एक रुपए 50 पैसे और डीजल पर एक रुपए 75 पैसा प्रति लीटर की दर से सेस संग्रहित किया जा रहा है। निधि के तहत 2004-05 से वर्ष 2023-24 तक 14384.50 करोड़ की निधि प्राप्त की गई, इसमें से दिसंबर 2024 तक 16176.75 करोड़ का व्यय किया गया है।

राज्य में मौजूद सड़क तंत्र (लंबाई कि.मी. में)

वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
राष्ट्रीय राजमार्ग	10790	0	0	0	10790
राज्य राजमार्ग	17325	4	19	28	17376
मुख्य जिला सड़के	14118	17	112	125	14372
अन्य जिला सड़के	53696	6020	198	8351	68265
ग्रामीण सड़के	160219	2681	40407	3031	206318
योग	256148	8702	40736	11535	317121

पीडब्ल्यूडी प्रदेश में 30 मार्च से शुरू कर कर है सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा

जयपुर। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की सड़कों के समुचित रखरखाव में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा निकालेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ मिल कर निकाली जा रही यात्रा 30 मार्च रविवार, वर्ष प्रतिपदा से शुरू होगी। इसे सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा के नाम से जाना जाएगा। यह यात्रा श्रीगंगानगर से प्रारम्भहोकर अधिकांश जिला केन्द्रों से होती हुई मई माह के मध्य में बुद्ध पूर्णिमा तक पूरी होगी। विभाग के मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के संयुक्त तत्त्वाधान में यह यात्रा निकाली जागी। यात्रा का उद्देश्य -दोष निवारण अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) के अन्तर्गत आने वाली चिन्हित सड़कों के बारें में अभियन्ताओं (सानिवि) एवं अध्ययनरत अभियान्त्रिकी छात्रों में जागरूकता बढ़ाना एवं सड़क सुरक्षा के तकनीकी विषयों के प्रति सामाजिक संवेदना जगाना है। इस यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले पौधारोपण 'सड़क सुरक्षा' एवं सड़कों के सामान्य गुणवत्ता निरीक्षण के मापदण्डों पर तकनीकी संवाद का आयोजन किया जाएगा। पोलिटेक्निक कॉलेज के छात्र इस यात्रा के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संवाद कर उन्हें जानकारी देंगे। दोष निवारण अवधि की सड़कों के निर्माण के समय ही उसके एक निश्चित समय तक रखरखाव करने का जिम्मा भी ठेकेदार का होता है। अच्छी गुणवत्ता की सड़कों के लिए यह शर्त लगाई गई है। लेकिन कई बार ये सड़कें समय से पहले ही खराब होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को इन सड़कों के क्षितग्रस्त होने पर किस तरह से विभाग तक जानकारी

पहुंचा सकते हैं यह बताया जाएगा। ताकि सड़कों को उनकी निश्चित अवधि व उसके बाद भी अच्छी स्थिति में बनाए रखा जा सके। श्रीगंगानगर से प्रारम्भ हो यात्रा बीकानेर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर नागौर, झुंझुनूं होते हुए हनुमानगढ़ तक पहुंचेगी।

जयपुर-किशनगढ़ हाइवे के अब सभी दस ब्लैक स्पॉट्स समाप्त

भांकरोआ फ्लाईओवर पर ट्रैफिक शुरू आमजन को मिलेगी जाम से राहत

जयपुर। जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाइवे पर भांकरोटा फ्लाईओवर मंगलवार को आमजन के लिए खोल दिया गया है। इससे आमजन को जाम से राहत मिलेगी। एनएचएआई के पीडी अजय आर्य ने बताया कि भांकरोटा फ्लाईओवर शुरू होने के साथ ही जयपुर से किशनगढ़ के बीच सभी 10 ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त कर दिया गया है। एनएचएआई के अनुसार जयपुर-किशनगढ़ हाइवे करीब 90 किलोमीटर लंबा हैं, जिस पर प्रतिदिन एक लाख से अधिक पैसेंजर कार यूनिट के ट्रैफिक मूवमेंट रहता हैं। पिछले चार साल में एनएचएआई की ओर से इस रूट पर 9 फ्लाईओवर बनाए जा चुके हैं। इनमें हीरापुरा, नर्सिंगपुरा, दहमीकलां, महलां, गाड़ोता, मोखमपुरा, सावरदा, पाड़ासली, बांदर सिंदरी फ्लाईओवर शामिल हैं।

31 मार्च तक थी डेडलाइन

एनएचएआई के अधिकारियों ने कोर्ट के समक्ष 31 मार्च तक भांकरोटा फ्लाईओवर के काम को पूरा करने पर सहमति दी थी, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते निर्धारित समय से छह दिन पहले ही भांकरोटा फ्लाई ओवर को आमजन के लिए खोल दिया गया।

पहले यहां ट्रैफिक सिग्नल था

भांकरोटा चौराहे पर पहले ट्रैफिक सिग्नल था, जिसे पार करने के लिए लोगों को दस से 15 मिनट तक का इंतजार करना पड़ता था। इस सिग्नल पर हादसे हो भी चुके हैं।

फोरलेन का कार्य अधूरा, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार

बालोतरा। बागुंडी से पचपदरा तक 22.1 किमी में चल रहे फोरलेन कार्य की धीमी गति को देखकर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने एनएच के अधिकारियों व संबंधित ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। बाड़मेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौर को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सड़क मार्ग से जा रही उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पचपदरा से निकलते ही निर्माणाधीन फोरलेन का कार्य धीमी गति से होने व मार्ग की हालत जर्जर होने पर गाड़ी रोककर नीचे उतरी। मौके पर एनएच के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 2022 में शुरू हुआ कार्य 24 तक पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक काफी कार्य बाकी पड़ा है। उन्होंने ठेकेदार को मौके पर बुलाकर लताड़ लगाई। वहीं समय पर काम पूरा होने पर नोटिस देकर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मौके पर कलेक्टर सुशील कुमार यादव को प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। करीब 15 मिनट तक उप मुख्यमंत्री ने एनएच के अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ ही कड़ी फटकार लगाते हुए समय पर काम पूरा करवाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की महत्वपूर्ण भेंट

जयपुर। जयपुर रिंग रोड, जोधपुर रिंग रोड, उदयपुर रिंग रोड आदि की डीपीआर के आदेश अगले महीने जारी किए जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-70 और राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के मौजूदा कनेक्शन को मजबूत और चौड़ा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के म्याजलार-जैसलमेर खंड और मुनाबाव-तनोट के सुंदरा म्याजलर अंबासिंह की ढाणी रोड भाग को पक्की सड़क के साथ 2-लेन का मजबूत और चौड़ीकरण करने के लिए 1237.71 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। राजस्थान को आगामी वर्ष में 5 हजार करोड़ के कार्य वार्षिक योजना में शामिल किए जाएंगे। सीआरआईएफ योजना में राजस्थान को 1500 करोड़ की राशि मिलेगी। भरतपुर रिंग रोड, एलिवेटेड रोड, और ब्रज चौरासी परिक्रमा की डीपीआर का कार्य अगले महीने से शुरू होगा। जयपुर-जोधपुर-पचपदरा रोड की डीपीआर का कार्य अगले महीने शुरू होगा। जयपुर-सीकर रोड का कार्य तेज गति से किया जाएगा। खाटू श्याम जी रिंग रोड एवं सुविधा विकसित करने के लिए डीपीआर के कार्य आदेश जल्द दिए जाएंगे। जयपुर किशनगढ़ हाईवे के सुदृढ़ीकरण हेतु डीपीआर तैयार की जाएगी। जयपुर दिल्ली पुरानी हाईवे का कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। शाहपुरा बाईपास के लिए डीपीआर के आदेश जल्द दिए जाएंगे। देसूरी की नाल पर डीपीआर का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा, और तत्पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं से राजस्थान में सड़क नेटवर्क का सुधार होगा, जिससे राज्य में यात्रा की सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

आरएसआरडीसी के पदाधिकारियों के विवरण व फोन नम्बर

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONST CORPN LTD.HQ EPABX: 2708717 (As on 20-2-2025)

Designation	Name	PABX	Office	Residence	Mobile No.
Chairman	Hon'ble Dy.CM Diya Kumari	301	3506301/2708717/ (RSRDC)/ 2926112		
Vice Chairman	Sh. Praveen Gupta	301	2227807	M. B., R No. 5208	I.P. No. 21537
P.A –(RSRDC)	Sh. Suresh Kumar	301/305	3506301,3506305/ 2708717		97850-24296
M.D.	Sh. Sunil Jai Singh	302	3506303,		98290-74022
P.A.-	Sh. Suresh kumar	303	3506303		97850-24296
Meeting Hall	Meeting Room	251	3506251		251
CFO	Sh. Devkinandan Sharma	320	3506352		94148-38007
PS-		332	3506332		
Chief Architect	Sh. Jitendra Purohit	310	3506310		94142-41688
G.M.	Sh. Satyendra Singh	306	3506307		94140-81273
CPM-I	Sh. Arvind K. Sahu	304	3506399		94143-10002
CPM-II	Sh. Anil Vijayvergiya	356			94140-41960
PA- (GM/CPM)		307/39	3506307/3506399		
DGM-Ajmer	Sh. Suresh Kumar Sharma		0145-2787789		91667-19725
DGM-Kota					
DGM Jodhpur	Sh. Yogendra Sharma				94143-75315
DGM (Admn.)	Sh. Neeraj Jain	311	3506311		79769-28813
DGM-I Jaipur	Sh. Anil Kr. Jain	333	3506333		94142-48124
DGM-II Jaipur	Sh. Sangeet Kumar	337	3506337		94140-17384
DGM-Elect. (Jpr)	Sh. Shiv Hare Mahaur	356	3506356		94144-67180
Sr. Architect	Sh. Sandeep Sarin	360	3506360		99285-20852
Co-Secretary	Smt. Madhuri Goyal	341	3506341		82095-95355
Sr. A.O (P)	Sh. Rakesh Gupta	384	3506384		98293-93214
Sr. A.O. (T)	Sh. Mayank Garg	398	3506398		94626-47533
Sr. A.O Pension	Sh. Balu Ram	368	3506368		94145-35770
Consultant (Arch)	Sh. S.K. Tekwani	328	3506328		94140-43898
M (Admn)	Sh. Haman Lal	314	3506314		80038-92777
M (Bldg.)	Sh. Parminder Singh	326	3506326		98292-00400
M (Enquiry)	Sh. Parminder Singh	324	3506309		98292-00400
M (Road)	Sh. Rajendra Meena	330	3506330		96944-41090
L.C.	Sh. S.K. Dixit	371	3506371		94144-68112
Sr. L. O	Sh. Gourav Choudhary	364	3506364		63780-21369
Stationery Store	Sh. Ali Khan	340	3506340		95494-42121
E & Y Consultant	Sh. Nilesh Patil	363	3506363	TeamLeader	77380-28044

Unit Offices

General Manager

1.	PD-Ajmer	Smt. Charu Mittal		0145		DGM-AJR	80580-46459
2.	PD-Tonk	Sh. Lokesh Gupta				DGM- Kota	94136-72540
3.	PD-Barmer	Sh. Saurabh Jain				DGM-JODH.	96601-16884
4.	PD-Jaisalmer	Sh. Mahendra Kumar				DGM-JODH.	94606-06083
5.	PD-Bikaner	Sh. Shilpa Kachhwaha		0151	[illegible]	DGM-II JPR.	98290-73719
6.	PD-Churu	Sh. Nikhil Mishra		015	[illegible]	DGM-II JPR.	94627-41189
7.	PD-Bhilwara	Sh. Narendra Choudhury			[illegible]	DGM-AJR	99835-29510
8.	PD-Chittorgarh	Sh. Shashank Sharma		0294	[illegible]	DGM-AJR	94602-36432
9.	PD-Jaipur-IV	Sh. Anish Bhatia	308	0141	[illegible]	DGM-I JPR	99280-23031
10	PD-Jodhpur-I	Sh. Manish Mathur		0291	[illegible]	DGM-JODH	94149-17653
11	PD-Jodhpur-II	Sh. Neeraj Soni		0291	[illegible]	DGM-JODH	97857-21026
12	PD-Pali	Sh. Rajeev Chhajer				DGM-JODH	98296-20766
13	PD- Sirohi	Sh. Rajeev Chhajer				DGM-JODH	98296-20766
14	PD-Sri Ganganagar	Sh. Nikhil Mishra				DGM-II JPR	94627-41189
15	PD-Udaipur	Sh. Lal Chand Verma		0294		DGM-AJR	95492-35818
16	PD-Banswara	Sh. Amit Garg				DGM-AJR	97851-89843
17	PD – Nagour	Sh. Praveen Soni				DGM-AJR	70147-88154
18	PD – Delhi	Sh. Anish Bhatia				DGM-I JPR	99280-23031

Chief Project Manager

1.	PD-Alwar	Sh. Manoj Srivastav				DGM-I JPR	94143-66892
2.	PD-Bharatpur	Sh. Rajendra Kr. Arora				DGM-I JPR	94147-16500
3.	PD- Dholpur	Sh. Santosh Kumar				DGM-I JPR	98873-32327
4.	PD-Sawai Madhopr	Sh. Rakesh Dixit				DGM (Admn.)	97999-99445
5.	PD-Jaipur-III	Sh. Mahendra Kumar Gupta	338	0141	3506338	DGM-II JPR	98296-31862
6.	PD- Jhalawar	Sh. Chandra Mohan Bairwa			[illegible]	DGM- Kota	94149-66568
7.	PD-Kota	Sh. Raj Kumar Rajoriya		074		DGM- Kota	82395-21285
8.	PD- Sikar	Sh. Mahipal Devanda		0294		DGM (Admn.)	96023-10084
9	PD -Jhunjhunu	Sh. Chander Mohan Vasudev				DGM (Admn.)	94145 08538
10	Baran					DGM- Kota	
11	PD- Jaipur –V	Sh. Vijay Kr. Gupta	322	014		DGM-II JPR	94140-72671
12	PD – Kota (Elect.)	Sh. Vinay Arya				DGM- (Elect.)	98290-46739

General Units

1.	PD Elect-I (Jaipur)	Sh. Pankaj Garg	Ext. 325	0141	3506325	DGM- (Elect.	98292-70940
2.	PD Elect-II (Jaipur)	Sh. Sanjay Kumar	Ext. 349	0141	3506349	DGM- (Elect.	94142-55963
3.	PD-Elect-Jodhpur	Sh. S.P. Bohra		0291		DGM- (Elect.)	94141-31553
4.	PD-(Q.C.) -I Jaipur	Sh. Omveer Singh Chahar	Ext. 366		3506366		80059-74196
5.	PD-(Q.C.) –II Jaipur	Hanuman Sahay Meena	Ext. 312				98798-23632 94144-46620
6	PD-(Q.C.) Jodhpur		Ext. 312			DGM-JODH	
7.	PD-Mechanical	Sh. D.K. Ponia	Ext. 321	0141	3506321		97820-19109

Toll Free No. = 1800-8914171

आरएसआरडीसी में कार्य विभाजन

Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45208RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

No. B-10(6) 25766-824 Date: 13-01-2025

OFFICE ORDER

In partial modification to previous order, the jurisdiction of GM/CPM-I,II/DY.G.M are hereby re-distributed as under: -

DGM I Jaipur	DGM II Jaipur	DGM Admin
Unit -V Jaipur	Unit - III Jaipur	Unit - Alwar
Unit - Kota	Unit - IV Jaipur	Unit - Bharatpur
Unit - Tonk	Unit - Sikar	Unit - Dholpur
Unit - Swaimadhopur	Unit - Churu	Unit - Jhunjhunu
Unit - Jhalawar	Unit - Bikaner	Unit - Delhi
Unit - Baran	Unit - Sriganganagar	

GM	CPM-I	CPM-II
DGM II, Jaipur (6 Units)	DGM Ajmer (6 Units)	DGM Jodhpur (6 Units)
Unit - Swai Madhopur	Unit - Tonk	DGM Admin (5 Units)
Unit - V, Jaipur	Unit - Kota	
	Unit - Jhalawar	
	Unit- Baran	

Jurisdiction of DGM Ajmer & DGM jodhpur will remain same as per previous order. DGM Electrical, DGM (Quality Control) and PD (Mechanical) will route the files through GM.

The bears approval of the Competent Authority.

(Sunil Jai Singh)
Managing Director

दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाना प्राथमिकता : एसई भूरी सिंह

जिले की सड़कों को बेहतर बनाए साथ ही दुर्घटना मुक्त भी : कलक्टर

अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह, पीडब्ल्यूडी

खैरथल। खैरथल सचिवालय पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भूरी सिंह, डीसीएमएचओ पूरणमल मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा, रिडकोर सहित परिवहन एवं आरएसआरडीसी के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कर कहा कि समन्वित प्रयास यह रहे कि जिले की सड़कें दुर्घटना मुक्त होवे। दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाना प्राथमिकता रहे। उन्होंने सुगम यातायात एवं दुर्घटना संभावित कारणों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह द्वारा बताई गई कार्य योजना पर जिला कलेक्टर ने फैटल एक्सीडेंट को प्रतिवर्ष 20 कम कर आगामी 5 वर्षो में शून्य करने के ओर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/नगर निकायों के पार्षद द्वारा अवैध कट से दुर्घटना संबंधित जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करने के लिए कहा ताकि स्थानीय स्तर पर ही आमजन के माध्यम से अवैध कट को पुनः खोलने वालों की सूचना प्रशासन तक पहुंच सके। उन्होंने नॉन पेचेबल सड़क के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए जिस पर अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह ने बताया कि

जिले के नॉन पेचेबल सड़क के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाएं जा चुके हैं। कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता को ब्लैक स्पॉट मार्गो पर अधिक साइन बोर्ड लगाकर यात्रियों को सजग करने के लिए कहा ताकि ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

उन्होंने खैरथल-तिजारा एवं भिवाड़ी के पुलिस अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि दुर्घटना की सूचना आईआरएडी (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस) पर दर्ज करवाना सुनिश्चित कराये। उन्होंने डिप्टी सीएमएचओ को जिले के सभी अस्पतालों को आईआरएडी पर मैप करने के निर्देश दिए। उन्होंने गत वर्ष तथा इस वर्ष में आईआरएडी पर रजिस्टर्ड दुर्घटनाओं संख्याओं की समीक्षा कर सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से आईआरएडी पर प्रत्येक दुर्घटना की एंट्री कराने के निर्देश दिए।

सभी मार्गों व शहरी सड़कों को दुरूस्त रखें : कल्पना

अधिशाषी अभियंता नीलम पूनियां, पीडब्ल्यूडी बानसूर

कोटपूतली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभिन्न मार्गो एवं शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिये। साथ ही बिजली विभाग से समन्वय कर मार्गो के बीच में लगे बिजली पोल्स का मौका मुआयना कर जल्द शिफ्ट करने को कहा। बैठक में जिला कलक्टर ने विभागवार विभिन्न योजनाओं और कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ बजट घोषणाओं सहित अन्य विकास कार्यो को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट अपडेट करें। उन्होंने बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिये संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की विभागवार समीक्षा करते हुये आवश्यक भूमि चिन्हिकरण व नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया हेतु शीघ्र आवेदन भिजवाने को कहा। उन्होंने घोषणाओं में जिले में बनाये जाने वाले जीएसएस, केवीएस, बस स्टैंड, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम, स्वयं सिद्धा आश्रम, वर्किंग वुमन हॉस्टल, साईबर थाने सहित अन्य घोषणाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध गुणवत्ता के साथ कार्य

संपादित करने को कहा। उन्होंने गत बजट 2024-25 की घोषणाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाईम में सुधार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आमजन को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, यह सुनिश्चित करते हुए स्थानीय स्तर पर ही संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करते हुये परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा करें व पोर्टल पर भी जानकारी अपडेट करें। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि मौसम में बदलाव को देखते हुये मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिये उपयुक्त उपाय सुनिश्चित करें। पर्याप्त दवा भंडार सुनिश्चित करते हुये अन्य तैयारियां पुख्ता रखें। उन्होंने बीमारियों की रोकथाम की निरन्तर मॉनिटरिंग करते हुये अस्पतालों में सुविधायें बढ़ाने, मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने एवं नियमित रूप से जनता क्लीनिकों एवं चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के निर्देश दिये।

आरएसआरडीसी व जेडीए की बानकी उपमुख्यमंत्री दिया ने बजट रिप्लाई में 80 करोड़ रुपए दिए

मुहाना मंडी जंक्शन पर 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा

जयपुर

जयपुर-भीलवाड़ा हाईवे पर सांगानेर स्थित मुहाना मंडी चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए फ्लाईओवर बनेगा। सांगानेर की तरफ से शहर में एंट्री वाले इस चौराहे के एक तरफ जयपुर-भीलवाड़ा आरएसआरडीसी दूसरी तरफ मुहाना मंडी का रास्ता निकलता है। भारी वाहनों का रूट होने से यहां हर वक्त जाम रहता है। मेगा हाईवे के इस जंक्शन पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) ने फ्लाईओवर का प्रस्ताव बनाया था। बजट रिप्लाई में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस चौराहे पर फ्लाईओवर की घोषणा कर सौगात दी है। इस पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आरएसआरडीसी के प्रस्ताव के अनुसार चौराहे पर 50 मीटर चौड़ा अंडरपास आरएसआरडीसी दोनों तरफ 300-300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर फोरलेन का होगा आरएसआरडीसी सांगानेर से भीलवाड़ा की तरफ आने-जाने वाले वाहन सीधे निकल सकेंगे। सांगानेर से मुहाना मंडी जाने वाले वाहन अंडरपास से गुजरेंगे। यह मेगा हाईवे जयपुर को रेनवाल, फागी, डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा आरएसआरडीसी भीलवाड़ा से सीधे जोड़ता है, लेकिन सांगानेर में जाम के चलते लोग इस रूट का इस्तेमाल नहीं करते। यहां से रोजाना करीब 2 लाख वाहन गुजरते हैं, जिन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी।

मालपुरा एलिवेटेड धरातल पर उतरा तो सांगानेर जाम फ्री

जेडीए ने सांगानेर थाने से मालपुरा गेट तक एलिवेटेड प्लान कर रखा है। यह एलिवेटेड प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो सांगानेर का करीब 3 से 4 किमी एरिया जाम फ्री होगा। यह पिछले बजट की घोषणा थी, मेट्रो रूट फाइनल होने के बाद इस पर काम शुरू होगा।

त्रिवेणी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड; टेंडर अप्रैल तक, जुलाई तक शुरू हो जाएगा काम

जेडीए गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट के लिए अप्रैल तक टेंडर निकालने की तैयारी कर रहा है। टेंडर प्रक्रिया के बाद जुलाई से प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। शहर में झोटवाड़ा, अजमेर रोड और सोड़ाला के बाद यह शहर की तीसरी एलिवेटेड रोड होगी, जो त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी सीधे जोड़ेगी।

4 तिराहे-चौराहों को जाम से राहत मिलेगी

यह प्रोजेक्ट 185 करोड़ रु. का है। ढाई किमी लंबे इस एलिवेटेड के बनने से 4 तिराहे-चौराहों को जाम से राहत मिलेगी। गोपालपुरा पुलिया टोंक रोड से गुर्जर की थड़ी तक का रास्ता 5 मिनट में पूरा होगा। अभी जगह-जगह जाम के चलते 15 से 20 मिनट लगते हैं। कई बार घंटों जाम लगा रहता है। इससे राहत मिलेगी।

3 लाख वाहन चालकों को होगा फायदा

यहां से रोजाना 2 से 3 लाख वाहन निकलते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रिद्धि-सिद्धि चौराहे, त्रिवेणी चौराहे आरएसआरडीसी महेश नगर कट पर रहता है। यहां से मानसरोवर, टोंक रोड और गुर्जर की थड़ी की तरफ जाने वाला ट्रैफिक निकलता है।

शाहपुरा (जयपुर) बाईपास निर्माण के लिए जल्द बनेगी डीपीआर : दिया कुमारी

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि शाहपुरा कस्बा (जयपुर) में यातायात जाम की स्थिति रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इस कस्बे में बाईपास बनाने की संभाव्यता की जांच करवाएगी।

शून्य काल के दौरान सदन के सदस्य श्री मनीष यादव द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस समस्या के निदान के लिए सभी उचित मापदंडों के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही शाहपुरा के बाहर से बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर बनाएगी।

भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि 178.44 करोड़ रुपए वितरित की जा चुकी -सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने शुक्रवार को विधान सभा में कहा कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण से काश्तकारों को उनकी भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि 178. 44 करोड़ रुपए वितरित की जा चुकी है। शेष काश्तकारों को मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। शून्य काल के दौरान सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री ने सदन के सदस्य चेतन पटेल कोलाना द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट कोटा-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस हाइवे में क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने बताया कि दीगोद तहसील क्षेत्र में इस सड़क परियोजना से प्रभावित मंदिरों की भूमि अवाप्त की गई जिसके मुआवजे की राशि देवस्थान विभाग उदयपुर (राज) को जमा करा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बने सड़क अंडरपास में बरसात का पानी जमा होने की समस्या का स्थायी समाधान एक्सप्रेसवे की ROW में कच्ची ड्रेन के माध्यम से कर दिया गया है।

आहोर में भवरानी से रोजियों की ढाणी तक सड़क निर्माण के लिए परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा : सार्वजनिक निर्माण मंत्री

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आहोर विधानसभा क्षेत्र में भवरानी से रोजियों की ढाणी तक सड़क निर्माण के लिए परीक्षण उपरान्त उचित निर्णय लिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। इससे पहले विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में हरजी-पचानवा नदी पर पुल, पादरली-तखतगढ़ पुल, कवराड़ा नदी पर पुल के लिए राशि रुपये 19.00 करोड़ की घोषणा 10 जुलाई 2024 को की गई। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य की कन्सलटेन्ट द्वारा डीपीआर राशि 34.65 करोड़ रुपये प्रस्तुत की गई है। जिसकी संशोधित राशि. 34.65 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक सहमति 10 फरवरी 2025 को जारी की जाकर निविदा प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि निविदा कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य को 15 माह में पूर्ण किया जाना संभावित है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि उक्त कार्यों के लिए राशि 34.65 करोड़ रुपये की संशोधित सैद्धांतिक सहमति 10 फरवरी 2025 को जारी कर दी गई।

बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस

पीडब्ल्यूडी ने डीपीआर बनाई, एनएचएआई नई डीपीआर बनाएगा या पीडब्ल्यूडी वाली ही मंजूर करेगा, यह अभी तय होना बाकी

बीकानेर। भजन लाल सरकार ने पिछले बजट में राजस्थान में पहली बार 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे एक साथ बनाने की घोषणा की थी। आर्थिक किल्लत डीपीआर बनते ही सामने आने लगी। आर्थिक कारणों से ही बीकानेर-कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का काम अब केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। संभावना है कि आने वाले समय में एक-दो और ग्रीन एक्सप्रेसवे केन्द्र के पाले में जा सकते हैं। केन्द्र के एक्सप्रेसवे बनाने से टोल की दर केन्द्र के हिसाब से ही होंगी। पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने एक साथ 9 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था। सभी की 2750 किमी से अधिक की लंबाई थी। इसके लिए डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ का टेंडर भी कर दिया गया। फर्म ने सर्वे भी शुरू कर दिया। दो दिन पहले जयपुर में हाई लेवल की मीटिंग हुई। उसमें सूचना दी गई कि अब बीकानेर-कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेसवे एनएचएआई बनाएगा। केन्द्र सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। तब बीकानेर के अभियंताओं ने सवाल किया कि फिर जो डीपीआर बनाई जा चुकी उस हिसाब से काम होगा या नई डीपीआर बनाई जाएगी। इसके लिए एनएचएआई को पत्र लिखने के लिए कहा गया। अगर एनएचएआई मौजूदा डीपीआर से संतुष्ट होगा तो इसी डीपीआर से काम शुरू होगा वरना नई डीपीआर बनाई जाएगी। पुरानी डीपीआर से काम हुआ तो उसमें बीकानेर से कोटपूतली के लिए तीन मार्ग सुझाए गए हैं। अगर एनएचएआई नई डीपीआर बनाएगा तो कुछ और भी बदलाव संभव हैं। नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद बीकानेर से कोटपूतली 295 किलोमीटर होगा। अभी जिस हाइवे से कोटपूतली जाते हैं उसमें 340 किलोमीटर दूरी और समय 6 घंटे लगता है। नए एक्सप्रेसवे से समय की भी बचत होगी क्योंकि करीब 3 से 4 घंटे में कोटपूतली पहुंचा जा सकता है। नए ग्रीन एक्सप्रेस-वे के निर्माण में करीब 11000 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। सरकार ने एक बार 10839 करोड़ मंजूर किए हैं।

बीकानेर के अभियंताओं का सुझाव, एक्सप्रेस-वे रिंग रोड के रूप में बने

जयपुर हुई हाई-लेवल मीटिंग में बीकानेर के अभियंताओं ने सुझाव दिया है। इसमें कहा गया कि नोखा से आते वक्त जोधपुर बाईपास टर्न से ग्रीन एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू हो और जैसलमेर हाई-वे की ओर जाए, वहां से श्रीगंगानगर बाईपास से होते हुए जयपुर बाईपास से कोटपूतली के लिए मुड़े। ऐसा होने से बीकानेर के लिए ये एक्सप्रेसवे रिंग रोड की तरह काम करेगा। पीडब्ल्यूडी इस एक्सप्रेस को बनाता तो ऐसा होने की संभावना थी लेकिन एनएचएआई बनाएगा तो ये प्लान शायद ही काम आए। हालांकि एनएचएआई के आरओ अत्री ने कहा कि उनके पास अभी तक कोई अधिकृत पत्र नहीं आया।

मौजूदा डीपीआर से काम हुआ तो ये हैं 3 विकल्प

पहला विकल्पः नोखा से आते वक्त जोधपुर बाईपास से बाई साइड से हाई-वे निकलेगा जो जैसलमेर हाई-वे श्रीगंगानगर हाई-वे की ओर से होते हुए नौरंगदेसर, श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, मंडावा होते कोटपूतली पहुंचेगा। इसकी दूरी करीब 288 किमी होगी।

दूसरा विकल्पः जयपुर-जोधपुर बाईपास के बीच से शुरू होगा जो नापासर, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, नीम का थाना होते हुए कोटपूतली पहुंचेगा। इसकी दूरी करीब 328 होगा। तीसरा विकल्पः ये जोधपुर बाईपास से शुरू होकर जसरासर, लक्ष्मणगढ़ होते हुए कोटपूतली पहुंचेगा जिसकी दूरी करीब 300 किमी होगी।

सरकार स्तर पर ऐसा विचार चल रहा है कि इस हाई-वे को केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बनाएगा। अब डीपीआर का क्या होगा, नई बनेगी पुरानी से ही काम चलेगा। ये जब फाइनल निर्णय होगा कि कौन एजेंसी बनाएगी तभी तय होगा।

– **केशराराम पंवार,** अधीक्षण अभियंता पीएचईडी एनएच

हाइवे निर्माण में सावधानियां जरूरी

सृष्टि में कोई भी जीव बिना पानी और भोजन के कुछ घंटों या दिन तक जीवित रह सकता है लेकिन थोड़े समय के लिए भी बिना सांस लिए रहना मुश्किल हो जाता है। जाहिर है जीवन की आधारभूत जरूरत शुद्ध हवा के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। सब-कुछ जानते-बूझते भी विकास की होड़ में पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। हरियाली पर लगातार चलाई जा रही कुल्हाड़ी के बीच चिंता की खबर यह है कि पिछले पांच साल के दौरान देश में हाइवे निर्माण के लिए करीब 57 लाख पेड़ों की बलि ले ली गई। उससे भी बड़ी चिंता यह कि इन काटे गए पेड़ों के बदले महज 3.28 लाख पौधे लगाए गए इनमें से भी एक चौथाई के नष्ट होने का अनुमान है।

इसमें दो राय नहीं कि पिछले वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हाइवे का, जो जाल बिछा है उससे आवागमन सुगम हुआ है। समय और श्रम की बचत होने लगी है सो अलग। आवागमन शुरू करने के लिए चौड़ी सड़कों की जरूरत भी है। हाइवे जब भी बनते हैं या सड़कों की चौड़ाई बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ आने वाले पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलती है। नियमानुसार हाइवे पर काटे गए पेड़ों की एवज में नए पौधे लगाकर पुरानी स्थिति में लाने का काम होना चाहिए। लेकिन यह देखने में आता है कि पौधे लगाने के नाम पर खानापूर्ति होकर रह जाती है। नीम, शीशम और सागवान जैसे पेड़ लगाने के बजाय हरियाली के नाम पर सजावटी पौधे लगाकर दायित्व की इतिश्री कर ली जाती है। ऐसे में पेड़ के बदले पेड़ लगाने का मकसद कागजों में ही रह जाता है। एक ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनियाभर में हरियाली बढ़ाने की चिंता की जा रही है। सरकारें भी अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर हाइवे बनाने के दौरान हरियाली के इस तरह के खात्मे को तो जीव हत्या का अपराध ही कहा जाएगा।

पेड़ों को जड़ सहित उठाकर दूसरी जगह लगाने की तकनीक भी पिछले सालों में इस्तेमाल होने लगी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। हाँ हाइवे निर्माण के दौर में पेड़ों को हटाना हो तो इन्हें दूसरी जगह शिट करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। बात सिर्फ हाइवे के किनारे आने वाले पेड़ों को हटाने की ही नहीं है। जहां तक संभव हो, आधारभूत सुविधाएं जुटाने के हर मामले में पेड़ों को सुरक्षित रखने के प्रयास होने चाहिए। हरियाली बचाने के लिए हाइवे की संरचना में जरूरी एहतियात बरतते हुए बदलाव भी किया जा सकता है।

जयपुर-दिल्ली हाइवे : परिवहन मंत्री ने उजागर किया टोल वसूली का सच

सड़क पर खर्चा 8919 करोड़ का, टोल वसूला ₹11945 करोड़

टोल वसूली और खर्च का हिसाब

नेशनल हाइवे खंड	टोल वसूली	लागत-रख रखाव खर्च
गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर	9218.30	6430.00
दिल्ली-गुड़गांव	2727.50	2489.45

(राशि करोड़ों रुपए में)

नई दिल्ली. देश में अच्छी सड़कों पर टोल के नाम पर लागत से ज्यादा कितनी उगाही कर रही हैं इसकी बानगी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिए लिखित उत्तर में खुद स्वीकार की। गडकरी ने बताया कि जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे (पुराना एनएच-8) पर पिछले 16 साल में सड़क परिवहन मंत्रालय ने 8919 करोड़ रुपए हाइवे पर खर्च किए हैं। जबकि टोल वसूली इससे कहीं ज्यादा 11945 करोड़ रुपए की हो चुकी है।

गडकरी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। बेनीवाल ने निर्माण लागत वसूलने के बावजूद टोल वसूली जारी रखने के साथ खस्ताहाल सड़कों पर टोल वसूली के औचित्य के बारे में सवाल पूछा था। लिखित जवाब में बताया गया कि नेशनल हाइवे पर टोल वसूली नियमों के तहत होती है। जो थोक मूल्य सूचकांक से अनुक्रमित नेशनल हाइवे की प्रति किलोमीटर आधार दर पर तय होती है। जयपुर से दिल्ली हाइवे के दो खंड हैं। गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड पर ज्यादा वसूली हुई है। जबकि इसके मुकाबले गुड़गांव-दिल्ली पर टोली वसूली कम है।

टोल शुल्क में छूट नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से इसकी निर्माण लागत से तुलना नहीं की जा सकती है। देश में भले ही हाइवे का जाल तेजी से फैल रहा हो, लेकिन टोल वसूली का मुद्दा भी बना हुआ है। हाइवे निर्माण की लागत निकलने के बाद भी टोल वसूली जारी रहने पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।

सबसे ज्यादा टोल वाला प्रदेश राजस्थान

देश के नेशनल हाइवों पर 1063 टोल नाके हैं, जिनमें से अकेले राजस्थान में 163 टोल नाके हैं। यह किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। इसके अलावा जयपुर-दिल्ली हाइवे पर स्थित शाहजहांपुर टोल नाका देश के सर्वाधिक टोल वसूली वाले नाकों में शुमार है

14 टोल प्लाजा एजेंसियों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल वसूली में गड़बड़ियों और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर 14 टोल प्लाजा एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनकी 100 करोड़ रुपए अमानत राशि जब्त कर ली है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में टोल वसूली में गड़बड़ी के बाद प्राथमिकी दर्ज कर इन एजेंसियों को नोटिस दिया गया था। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।

पिछली सरकार में राय तक नहीं लेते थे : दिया

सड़कों पर विपक्षी विधायकों की सिफारिश के मुद्दे पर जूली और डिप्टी सीएम के बीच बहस

जयपुर. सड़कों की मंजूरी में विधायकों की सिफारिश के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बहस हुई। जूली ने इस मामले में विपक्षी विधायकों की सिफारिश नहीं चलने की बात कही और मुख्यमंत्री के विधायकों की सिफारिश वाला वादा याद दिलाया। इस पर दिया ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में उनके विधायकों से राय तक नहीं ली जाती थी, लेकिन अब सड़कों की रिपेयर कमेटी की सिफारिश के आधार पर और जनप्रतिनिधियों की राय से किया जाएगा। विधायक किसी भी सड़क की रिपेयर या नई सड़क का काम बताएंगे तो परीक्षण के बाद मंजूर करेंगे।

इस तरह बहस तक पहुंचा मामल

जूली ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में कहा था कि विधायक जो प्रस्ताव देंगे उसके बाद सड़कें मंजूर करेंगे। आप कमेटी की जगह विधायकों की राय से सड़कें मंजूर करें। दिया ने कहा मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूं। अगर कोई ऐसी सड़क है तो कमेटी को भेज दें। मुझे भी भेजेंगे तो पूरा परीक्षण कराकर ऐसी सड़क को रिपेयर भी करवाएंगे। नई सड़क भी बनाएंगे। जूली फिर बोले आप तो यह बताओ कि मुख्यमंत्री ने सदन में जो बात कही है उसकी पालना करवाएंगे क्या? दिया ने कहा कि मैं भी वही आश्वासन दे रही हूं, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा विधायक की सिफारिश पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कमेटी विधायकों को नहीं मानेगी, वह सभी के सुझाव लेगी।

केसरपुर में चारदीवारी और सड़कें ध्वस्त

भाजपा नेता की अवैध प्लॉटिंग पर दूसरे दिन भी चले बुलडोजर

अलवर। जयसमंद बांध के पास भाजपा नेता की ओर से की गई अवैध प्लॉटिंग पर दूसरे दिन भी यूआइटी ने बुलडोजर चलाए। कार्रवाई के दौरान चारदीवारी व सड़कें ध्वस्त की गईं। आस-पास 50 से ज्यादा भवन बन गए, जिनमें बसावट हो गई। उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी मार्ग पर दो अन्य जगहों पर भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई एक-दो दिन में होगी। राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा समेत खटाना सिंह, भोपाल सिंह, रूप सिंह डेरा व हीरालाल गुर्जर ने केसरपुर में करीब 25 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की थी। साथ ही आस-पास अन्य लोगों ने भी अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी। यह मुद्दा राजस्थान पत्रिका ने उठाया और लोगों ने जिला प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तक पहुंचाया, उसके बाद कार्रवाई की गई। गुरुवार शाम 5 बजे तक यह कार्रवाई चली। ग्रेवल सड़कों को उखाड़ा दिया, जहां बसावट थी, वहां की सड़कें उखाड़ने से रास्ते अवरुद्ध हो गए। यूआइटी के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अनिल शर्मा का कहना है कि कृषि भूमि का भू-रूपांतरण नहीं कराने पर कार्रवाई की गई है।

राजेन्द्र गुर्जर, अतुल कुमार व राजेश व्यास को निजी सचिव के पद पर पदोन्नति

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, P.W.D.,RAJASTHAN, JAIPUR

No. Sec. I/B/2025/96 **Dated. 08 .03.2025**

OFFICE ORDER

The Following substantive Additional Private Secretary who have been promoted to the post of Private Secretary against the vacancy for the year 2024-25 vide this office order No. Sec. I/B/2025/82 dated 27.02.2025 are hereby posted as shown against him with immediate effect :-

S. No.	Name (Sarv Shri)	From	To
1	Sh. Rajendra Kr. Gujar	Chief Engineer's Office, Jaipur	Chief Engineer's Office, Jaipur
2	Sh. Atul Kumar	Circle Dholpur	Chief Engineer's Office, Jaipur
3	Sh. Rajesh Vyas	Circle Pali	Zone-I, Jodhpur

The aforesaid officials will join there new place of posting within a period of 15 days from the date of issue of this posting orders , otherwise there promotion orders will automatically be stand cancelled. In case they do not join their new assignment and wants to forgo the chance of promotion, they should furnish an undertaking to this effect through there controlling officer with a copy direct to this office within prescribed time limit. On forgoing the chance of promotion action will be taken in accordance with the Finance Department (Rules Division)'s order No.F.14(88) FD(Rules)/2008-II dated 31.12.2009.

The above officials will draw there pay as per recommendation of 7th pay commission of the above post with usual allowances as admissible under Rules, from the date of their joining on promotion post.

The concerning office shall intimate there date of relieving/joining to this office immediately.

Signature valid
Digitally signed by T... Chand Gupta
Designation: ... Engineer
Date: 2025.03.... 3:27:56 IST
Reason: Approved

e-signature
(T.C. Gupta)
CHIEF ENGINEER & AS,P.W.D
RAJA STHAN JAIPUR

आसीन्द में बाइपास से खारी नदी तक सड़क निर्माण के लिए परीक्षण करवाकर निर्णय लिया जाएगा : दीया कुमारी

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि आसिन्द शहर में नए निर्मित बाइपास से खारी नदी तक सड़क निर्माण के लिए परीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि व्यवहारिक होने पर शीघ्र ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछेगए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने बताया कि उपखण्ड आसीन्द के रघुनाथपुरा से शम्भूगढ़ वाया आसीन्द सड़क तथा नेशनल हाईवे 148 डी व 158 डी सोपुरा से महाराजपुरा चौराहे को स्टेट हाइवे 133 से जोड़ने वाली सड़क पर नवीन सर्विस रोड़ का कार्य शुरू हो गया है। इससे पहले विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड आसीन्द के रघुनाथपुरा से शम्भुगढ़ वाया आसीन्द मय कॉजवे (आसीन्द) भीलवाड़ा सड़क के 27 किलोमीटर में से 8.00 किलोमीटर लम्बाई में सड़क अच्छी स्थिति में है। शेष रहे 19 किलोमीटर सड़क के रिपेयर तथा उन्नयन हेतु बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिन्दु संख्या 15(छ) की क्रम संख्या 65 के अनुसार राशि 8.10 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र आसीन्द में नेशनल हाईवे 148 डी व 158 डी पर सोपुरा जंक्शन (आसीन्द) (किमी 67/930) से महाराजपुरा जंक्शन (आसीन्द) स्टेट हाईवे 75 (किमी 74/630) के मध्य की दूरी 6.7 किलोमीटर में दो लेन मय पेव्ड शोल्डर डामर सड़क है। इस सड़क पर 6.7 किलोमीटर में से 1.70 किलोमीटर लम्बाई में चिह्नित आबादी क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ आवश्यकतानुसार सर्विस रोड़ निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इसमें से 1.00 किलोमीटर सर्विस रोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 0.70 किलोमीटर लम्बाई में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि भूमि अवाप्ति के पश्चात सर्विस रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित है। शेष 5.00 किलोमीटर लम्बाई में आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण सर्विस रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

मॉडल कोई भी हो जनता से वसूलेंगे टोल, हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार

जयपुर-जोधपुर और बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे केंद्र करेगा पूरा, डीपीआर का काम सौंपा

जयपुर। राजस्थान में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस-वे का निर्माण किस मॉडल पर होगा, अभी तय होना बाकी है, बजट में इनकी अनुमानित लागत 60 हजार करोड़ आंकी गई है और एक्सप्रेस-वे का निर्माण हाईब्रिड एन्युटी मॉडल और बीओटी पर करने की घोषणा की गई है। हालांकि मॉडल कोई भी हो, लेकिन जनता से टोल वसूला जाएगा। वर्तमान में इनकी 30 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। ये एक्सप्रेस-वे उन जगहों पर बनाए जाएंगे, जहां पहले कोई सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, हरे-भरे खेतों से होकर गुजरेंगे।

क्या होता है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन्हें हरे मैदानों या खेतों के बीच से निकाला जाता है, जहां भूमि अधिग्रहण आसान होता है. साथ ही जमीन समतल होती है और शहर से थोड़ा दूर होने के कारण भीड़-भाड़ भी कम होती है. इसलिए इन एक्सप्रेस-वे को बनाना और फिर यहां उच्च गति पर वाहन का परिचालन करना आसान होता है। एक्सप्रेस-वे को शहरों के बीच से कम ही निकाला जाता है। इसके कारण इनमें घुमाव और मोड बहुत कम होते है।

दो एक्सप्रेस-वे पर एनएचएआई की मंजूरी

केंद्र सरकार के विजन 2047 के तहत दो नशीब फील्ड एक्सप्रेस-वे पर एनएचएआई ने सहमति प्रदान कर दी हैं। पहला जयपुर से जोधपुर और दूसरा बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे शामिल है। हालांकि राज्य की ओर से अब केंद्र को पत्र लिखकर सभी नौ एक्सप्रेस-वे का काम हाथ में लेने का आग्रह किया जा रहा है।

इसके क्या फायदे

हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत सरकार डेवलपर को परियोजना में होने वाले खर्च का 40 फीसदी भुगतान कार्य प्रारंभ होने से पहले ही कर देती है, जबकि शेष 60 फीसदी राशि डेवलपर को खुद की लगानी होती है, यह अब तक अपनाए जा रहे बीओटी मॉडल से बेहतर है, क्योंकि इसमें डेवलपर को काम शुरू करने के लिए वित्तीय संस्थानों से वित्तीय मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। एडवांस राशि खर्च होने तक डेवलपर शेष 60 प्रतिशत राशि का जुगाड़ कर लेता है।

राजस्थान ने क्यों अपनाया एचएएम

वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते राजस्थान सरकार ने हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर फोकस किया है। 2750 किलोमीटर लंबे नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए राज्य सरकार के पास 60 हजार करोड़ की वित्तीय प्रबंधन नहीं होने के कारण इस मॉडल पर फोकस किया है ताकि कम समय में तुरंत रिजल्ट मिल सके।

एचएएम मॉडल की अब तक सफलता के उदाहरण...

- 2016 से 2021 के बीच 250 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एचएएम के तहत निविदाएं जारी की गई।
- 2017 में गंगा नदी बेसिन के दो प्रमुख शहरों वाराणसी और हरिद्वार में सीवरेज प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार एचएएम को अपनाया गया।
- 2022-23 के बजट में भारत के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर देने के बाद भारत सरकार ने इसे महत्वपूर्ण बनाया।
- शुरुआत में एनएचएआई ने 1900 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं में से लगभग 15 प्रतिशत परियोजनाएँ एचएएम के तहत मंजूरी दी थी

राजस्थान के लिए फायदे

- सार्वजनिक धन का सही तरीके से इस्तेमाल।
- तेज गति से निर्माण और
- बेहतर गुणवत्ता।
- निजी कंपनियों के लिए कम वित्तीय दबाव।
- भविष्य में सड़क के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सरकार द्वारा निभाई जाएगी।

हाईब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है...?

हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल में सरकार और निजी कंपनियों का संयुक्त निवेश होता है। यह मॉडल राज्य और केन्द्र सरकार के बीच साझेदारी की तरह काम करता है, जिसमें निजी कंपनियां निर्माण कार्य करती हैं और उन्हें सरकार से तय की गई एन्यूटी राशि मिलती है। यहां सरकार निर्माण का कुछ को अनिश्चित समय तक हिस्सा और ऑपरेशन का कुछ हिस्सा तय करती है और निजी कंपनियों अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है।

बीओटी मॉडल क्या था ?

बीओटी मॉडल में निजी कंपनियां सड़ कों का निर्माण करती और कुछ समय तक उन्हें चलाने का अधिकार प्राप्त होता था। इस दौरान ये टोल से पैसा कमाती थी। अंत में सड़क को सरकार को ट्रांसफर कर देती थी। यह मॉडल कुछ मामलों में समस्याओं का सामना करता था, जैसे कि देर से निर्माण, परियोजना की लागत में वृद्धि और वित्तीय बोड का भार हो जाता था।

15 जिलों में नेटवर्क होगा तैयार

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इन एक्सप्रेस हाइवे की घोषणा की। इन रूट में हालांकि बाद में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के निर्धारित रूट के अनुसार ये एक्सप्रेस-वे 15 जिलों से होकर गुजरेंगे, जिनमें आवाजाही में लगने वाला घंटों का समय आधे से भी कम हो जाएगा।

ये है नौ पैकेज प्रस्तावित

जगह का नाम	लागत	प्रस्तावित लंबाई किमी	जमीन अधिग्रहण
कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे	6906 करोड़	181 किलोमीटर	1679 हैक्टेयर
जयपुर-भीलवाड़ा एक्सप्रेस-वे	6894 करोड़	193 किलोमीटर	1777 हैक्टेयर
बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे	10839 करोड़	295 किलोमीटर	--
ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे	14010 करोड़	342 किलोमीटर	3165 हैक्टेयर
जालौर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे	16267 करोड़	402 किलोमीटर	3618 हैक्टेयर
अजमेर-बांसवाड़ा एक्सप्रेस-वे	12582 करोड़	358 किलोमीटर	--
जयपुर-फलौदी एक्सप्रेस-वे	11112 करोड़	345 किलोमीटर	--
श्रीगंगानगर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे	12049 करोड़	290 किलोमीटर	2700 हैक्टेयर
जयपुर-जोधपुर वाया पचपदरा एक्सप्रेस-वे	--	344 किलोमीटर	--

(शेष अगले पृष्ठ पर...)

ये समझना जरूरी...

1. हाईब्रिड ऐन्युइटी मॉडल के तहत सरकार और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी की मुख्य भूमिका क्या होती है?

इसका उद्देश्य निर्माण के खर्च और जोखिम को दोनों पक्षों के बीच बांटना है। जहां सरकार सुनिश्चित राशि का भुगतान करती है। वहीं निजी कंपनियां सड़क के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी उठाती है। दोनों पक्षों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामंजस्यपूर्ण कार्य संचालन सुनिश्चित करता है।

2. क्या हाईब्रिड ऐन्युइटी मॉडल में टोल टैक्स की भूमिका घट जाती है?

हां हाईब्रिड ऐन्युइटी मॉडल में निजी कंपनियों को टोल से ज्यादा आय की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि सरकार उन्हें एक निश्चित ऐन्युइटी राशि का भुगतान करती है। इसका मतलब यह है कि टोल कलेक्शन पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है।

3. क्या हाइब्रिड ऐन्युइटी मॉडल से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ेगा ?

इस मॉडल से गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर प्रोजेक्ट के निर्माण, रख-रखाव और ऑपरेशन को नियंत्रित करेंगे। इसके अलावा हाईब्रिड ऐन्युइटी मॉडल में समय-समय पर निगरानी की जाती है, जिससे गुणवत्ता बनी रहती है।

4. क्या यह मॉडल राज्यों में भी अपनाया जा सकता है?

हां, यह मॉडल अन्य परियोजनाओं, जैसे कि रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अपनाया जा सकता है। इसके फायदे और संरचना के कारण, यह मॉडल अधिक स्थिरता और निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकता है।

हाईब्रिड एन्युटी मॉडल और बीओटी के बीच अंतर

निवेश का तरीका बीओटी में निजी कंपनियां पूरी लागत उठाती थीं, जबकि हाईब्रिड एन्युटी मॉडल में सरकार और निजी कंपनी दोनों का संयुक्त निवेश होता है। वित्तीय जिम्मेदारी बीओटी में प्राइवेट कंपनियों को पूरे टोल के जरिए पैसा कमाना होता था, जबकि हाईब्रिड एन्युटी मॉडल में सरकार एक निश्चित समय तक नियमित ऐन्युटी भुगतान करती है।

समय और रिस्क: बीओटी में निजी कंपनियों को सभी रिस्क उठाने होते थे, जबकि हाईब्रिड ऐनुइटी मॉडल में रिस्क साझा होता है, जिससे प्राइवेट कंपनियों पर कम दबाव पड़ता है।

नया मॉडल अपनाने के पीछे मुख्य कारण वित्तीय दबाव कम होना: हाईब्रिड ऐनुइटी मॉडल में सरकार का हिस्सा बढ़ने से निजी कंपनियों के लिए जोखिम कम हो जाता है।

समयबद्ध विकास: यह मॉडल परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

सरकारी सहयोग: सरकार की ओर से नियमित ऐनुइटी भुगतान करने से परियोजना पूरी होने के बाद भी सड़क के संचालन के दौरान सार्वजनिक लाभसुनिश्चित होता है।

हाईब्रिड एन्युटी मॉडल एक नया कॉन्सेप्ट हा है, जिस पर सरकार को भी एक साथ वित्तीय भार नहीं आता। इस मॉडल में कंपनी की हाइवे मेंटीनेंस की अवधि भी ज्यादा होती है, जो जनता के लिए फायदेमंद हैं। देश में कई एनएच इस मॉडल पर बन रहे हैं।

- के.सी. मीणा, उपाध्यक्ष, इंडियन रोड कांग्रेस

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के आठ पैकेज के लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद तय होगा कि इनका काम किस मोड पर हाथ में लिया जाएगा।

सतीश चन्द्र अग्रवाल, मुख्य इंजीनियर (एन.एच.), पीडब्ल्यूडी

जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस वे

थोड़ा इंतजार...दिल्ली दूर नहीं साढ़े तीन घंटे का होगा सफर

नवंबर 2024 में पूरा होना था एक्सप्रेस वे का काम, अब मई तक होने की उम्मीद

जयपुर। आपका दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से दिल्ली आना-जाना रहता है और जयपुर से बांदीकुई 67 किलोमीटर चार लेन एक्सप्रेस वे के पूरे बनने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। करीब दो माह बाद जयपुर से दिल्ली की दूरी करीब तीन से साढ़े तीन घंटे में तय की जा सकेगी। मई तक एक्सप्रेस वे के बनकर तैयार होने की उम्मीद है। एक रेलवे ओवर ब्रिज को छोड़ अन्य कार्य एक माह में पूरे हो जाएंगे। यदि एनएचएआई आंशिक रूप से एक्सप्रेस वे को खोल देती है तो अप्रेल में भी वाहनों का संचालन हो सकता है। लेकिन, यह सब रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से ही तय हो पाएगा।

लगे रफ्तार के साइन बोर्ड

एक्सप्रेस वे पर स्पीड के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कार के लिए एक्सप्रेस वे पर अधिकतम 120 की स्पीड रखी गई है (यही स्पीड दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर भी है)। वहीं बड़े वाहनों यानी बस, ट्रकों के लिए स्पीड 80 रखी गई है। दोपहिया वाहन यहां नहीं चलेंगे। आगरा रोड पर बगराना के पास रिंग रोड से एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है और बांदीकुई के पास दिल्ली- मुम्बई एक्सप्रेस वे से इसे कनेक्ट किया है।

जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस वे एक नजर में

- एक्सप्रेस वे की लंबाई 67 किमी है। बांदीकुई से सोहना तक एक्सप्रेस वे की लम्बाई 167 किमी है।
- जयपुर से सोहना तक 234 किमी हिस्से पर छोटे वाहन 120 किमी की रफ्तार से चल सकेंगे।
- एक्सप्रेस वे बनने के बाद दिल्ली की दूरी 20 किमी कम हो जाएगी, उससे 30 से 35 मिनट कम लगेंगे।
- दिल्ली - मुम्बई एक्सप्रेस वे को एनई 4 नम्बर से जाना जाता, जयपुर -बांदीकुई एक्सप्रेस वे को 4 सी के नाम से जाना जाएगा।
- नायला, आंधी, मनोहरपुर -दौसा रोड, बांदीकुई पर उतरा जा सकेगा।
- बांदीकुई में एक्सप्रेस वे पर और जयपुर में बगराना में क्लोवर लीफ का काम इसी माह पूरा हो जाएगा।
- क्लोवर लीफ, रेलवे ओवर ब्रिज को छोड़ छोटे -मोटे काम को छोड़ दें तो यह एक्सप्रेस वे बन कर तैयार है।
- इसको नवम्बर 2024 तक बन जाना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, रेलवे की अनुमति से काम पूरा होने में समय लग रहा है।

कोल्वा में रेलवे ट्रैक के ऊपर बन रहे ब्रिज में लग रहा समय

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से तीन किलोमीटर पहले कोल्वा गांव के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज को पूरी तरह से तैयार होने में अभी करीब दो माह लगेंगे। एक तरफ के हिस्से को एक से डेढ़ माह में तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस एक्सप्रेस वे पर यातायात चालू किया जा सके। यहां काम कर रहे सेफ्टी इंजीनियर संजीव कुमार ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर दो लेन में से एक लेन तो एक से डेढ़ माह में तैयार कर देंगे। एक लेन में दो माह लगेंगे।

वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए खुशखबरी

सरिस्का में जल्द खुलेंगे दो नई सफारी ज़ोन

टूरिस्ट कंपलेक्स का भी होगा कायाकल्प

आईएफएस अभिमन्यु सहारण के बढ़ते कदम से बढ़ेगा सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन

आईएफएस श्री अभिमन्यु सिंह सहारण
उप वन संरक्षक, सरिस्का बाघ परियोजना

डॉ सौरभ माथुर

राजस्थान के सबसे पसंदीदा जंगल सफारी पर्यटन स्थलों में से एक है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो नई सफारी जॉन खोलने के लिए तेजी से काम चल रहा है, सरिस्का के उप वन संरक्षक श्री अभिमन्यु सहारण ने भारतीय न्यूज संपादक डॉ सौरभ माथुर को बताया कि फिलहाल सरिस्का में पर्यटकों की सफारी के लिए 3 ज़ोन ऑपरेशनल है लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सरिस्का बाघ परियोजना में दो नए जोन खोले जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे तथा वन विभाग की भी आय में बढ़ोतरी हो जिससे कि सरिस्का बाघ परियोजना को और सुदृढ़ तरीके से चलाने में सहायता मिलेगी, श्री सहारण ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित टूरिस्ट कांप्लेक्स में भी सुविधा बढ़ाने पर काम चल रहा है जहां आने वाले समय में पर्यटकों को बेहतर कैंटीन, वेटिंग लाउंज इत्यादि समेत कई नई सुविधा मिलेगी जिससे दूर दराज से आ रहे पर्यटकों को जंगल सफारी करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री सहारण ने बताया की 2008 से पहले शून्य हो चुके सरिस्का टाइगर रिजर्व में फिलहाल 29 वयस्क बाघ तथा 12 शावक मौजूद है जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके अलावा सरिस्का बाघ परियोजना में गर्मियों को देखते हुए कच्चे व पक्के जल स्रोत का निर्माण भी युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है जिसमें अब बोरिंग के माध्यम से वन्यजीवों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, इतना ही नहीं नई सफारी जोन के लिए रास्तों को जोड़ने का काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है, आपको बता दें कि नई दिल्ली के पास में होने की वजह से उत्तर भारत का अधिकतर पर्यटक सरिस्का को ही अपनी पसंदीदा जंगल सफारी डेस्टिनेशन मानता है इसीलिए भारी तादाद में पर्यटक सरिस्का आना पसंद करते हैं, उम्मीद है आईएफएस श्री अभिमन्यु सहारण के नए प्रयासों से सरिस्का बाघ परियोजना को नई पहचान मिलेगी तथा इस परियोजना का नाम पूरे देशभर में नई ऊंचाइयों को छूएगा।

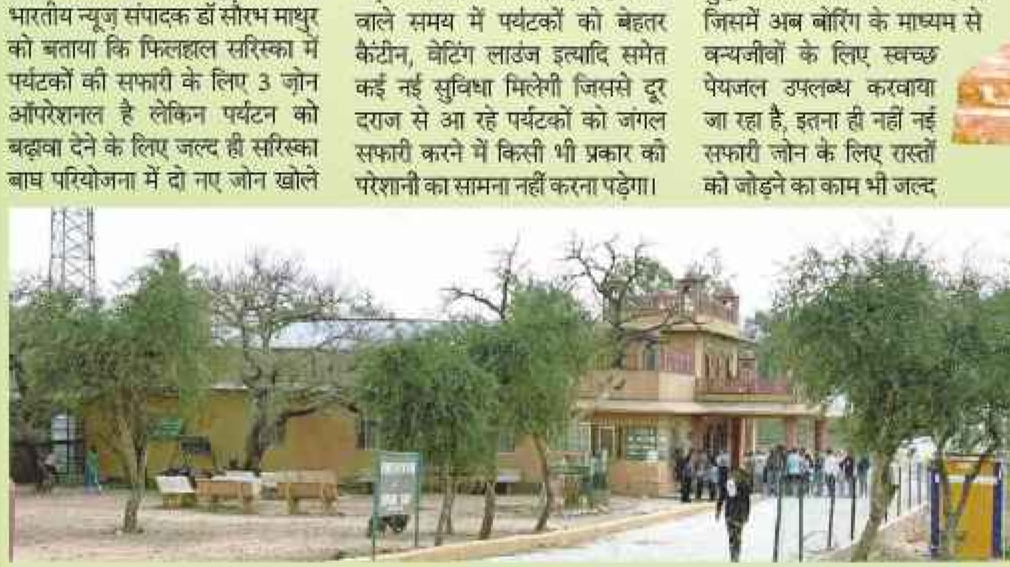

बे-मिसाल बेनीवाल

आंधियों के बीच जो
जलता हुआ मिल जाएगा
उस दिए से पूछना,
पता मेरा मिल जाएगा

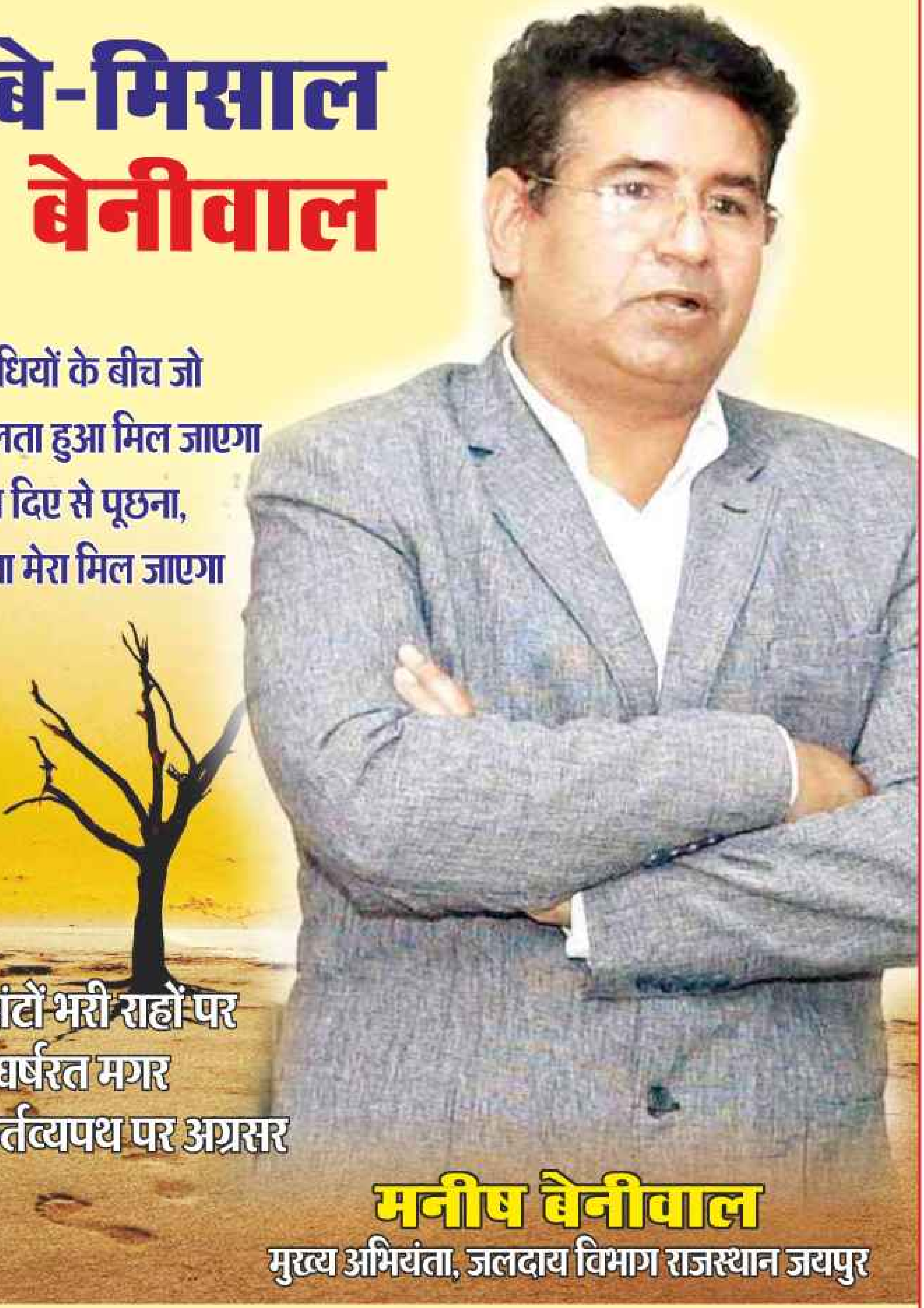

कांटों भरी राहों पर
संघर्षरत मगर
कर्तव्यपथ पर अग्रसर

मनीष बेनीवाल

मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग राजस्थान जयपुर

करते हैं कमाल
डूंगरराम मेघवाल

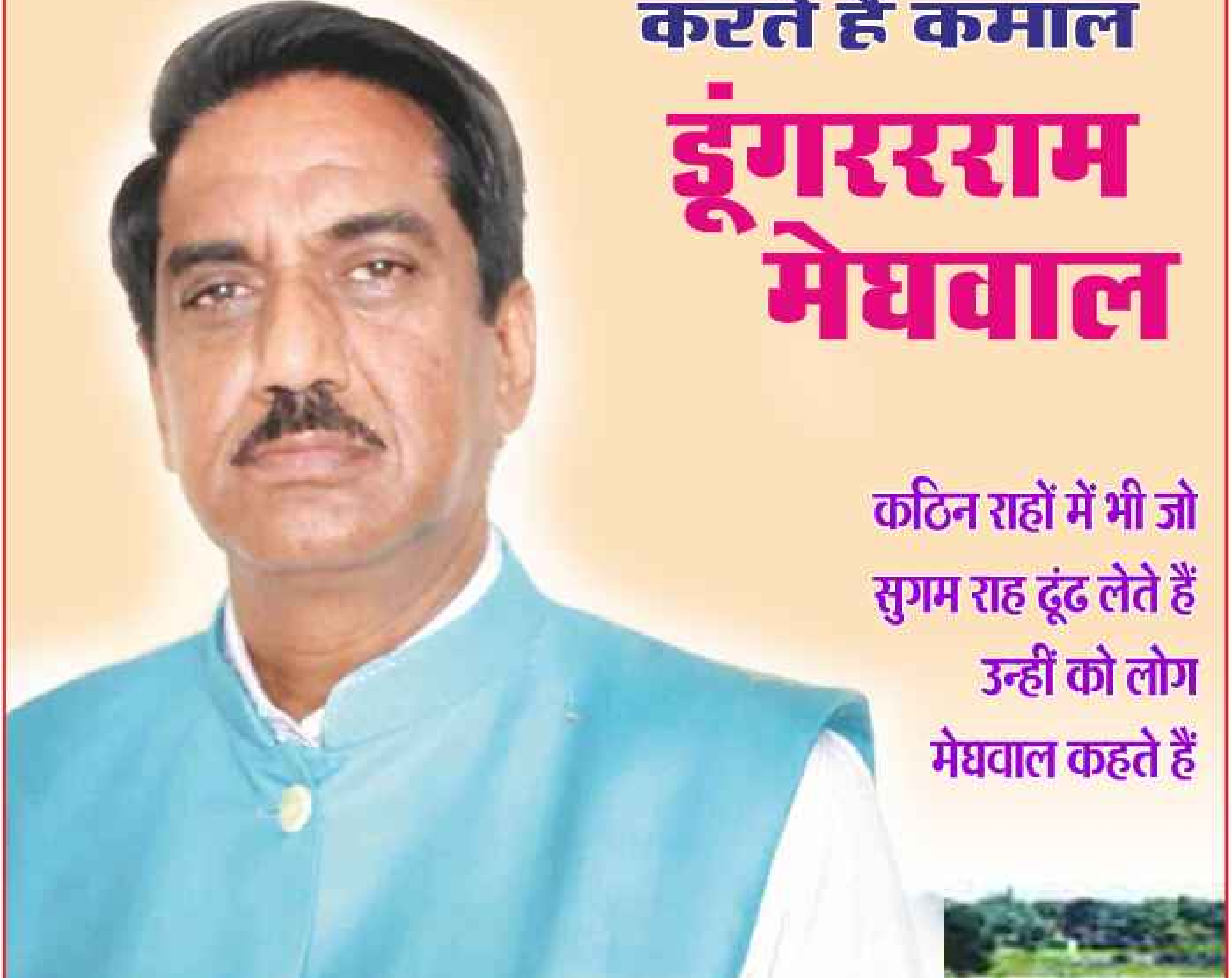

कठिन राहों में भी जो
सुगम राह ढूंढ लेते हैं
उन्हीं को लोग
मेघवाल कहते हैं

जातिवाद से दूर एवं
जटिल समस्याओं का
समाधान कर
राज्य हित में कार्यरत

डूंगरराम मेघवाल

सचिव, पीडब्ल्यूडी, राजस्थान जयपुर

आरटीडीसी सरिस्का 'टाइगर डैन' का काया कल्प

पर्यटकों को खूब लुभा रहे रिनोवेटेड कमरे

आरटीडीसी की एमडी श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने सरिस्का, सिलीसेड पर्यटन क्षेत्र का अवलोकन किया। टाइगर डैन होटल में इकाई के कर्मचारियों एवं मैनेजर श्री विक्रम सिंह सिसिंवार (फोटो में मैडम के बांयी ओर) के साथ निरीक्षण करते हुए। इस अवसर पर हमारी जिन्दगी मैगजीन की प्रति संपादक सौरभ माथुर द्वारा भेंट करने के उपरांत स्टाफ से मैगजीन की प्रशंसा करते हुए। जो उनके हाथों में है।

पर्यटन क्षेत्रों के दौरे पर गए भारतीय न्यूज एवं हमारी जिन्दगी मैगजीन के प्रतिनिधि डॉ. सौरभ माथुर ने भी व्यवस्थाएं देखी।

पिछले दो साल से राजस्थान टूरिज्मडिपार्टमेंट कारपोरेशन अपने सभी होटलों की कायाकल्प करने में जुटा हुआ है जिसके नतीजे उत्साहित कर देने वाले दिख रहे हैं जहाँ अपग्रेड हुए कमरों में पर्यटक आनंद ले रहे हैं तो वहीं विभाग के सभी होटलों में पर्यटक वापस रुचि लेने लगे हैं , इसी प्रकार से राजस्थाब के सरिस्का में स्थित होटल टाइगर डैन में भी 15 कमरें रिनोवेट किए गए हैं जिसकी आलीशान साज सज्जा पर्यटकों का मन मोह ले रही है, आपको बतादें इस पूरे क्षेत्र में इस होटल जैसी लोकेशन और किसी भी होटल या रिसोर्ट की नहीं है। 21 कमरों की इस विशालकाय प्रॉपर्टी में आलीशान गार्डन के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, बार और रेस्टोरेंट का भी लुत्फ़ पर्यटक उठा रहे हैं। भोर होते ही होटल में हिरण अठखेलियां करते हुए चले आते हैं और नज़ारा देखते ही बनता है। होटल मैनेजर श्री विक्रम सिंह सिसिंवार का कहना है कि हम हर प्रयास करते हैं जिससे हमारे यहाँ आने वाले पर्यटक एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, उनका कहना है कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी को रिनोवेट करने के बाद पर्यटक यहां खिंचे चले आ रहे हैं इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि इस होटल को अच्छे से व्यवस्थित रखें। उन्होंने बताया कि वो और उनकी पूरी टीम होटल को मैंटेन करने में किसी भी छोटी-मोटी कमी को अपने ही स्तर पर तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष भी सीजन में बहुत सारे पर्यटकों को इस होटल ने रिझाया और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस होटल का बिज़नेस नई ऊंचाईयों को छुएगा।

आपको बता दें कि इस होटल के 15 कमरों को बिलकुल नए तरीके से सजाया गया है जहां 52 इंच के स्मार्ट एलईडी टीवी समेत उच्चकोटि की ईंटीरियर डिजाइनिंग की गई है तथा पूल टेबल को भी सजाकर गेम ज़ोन भी शुरू कर दिया गया है। सरिस्का टाइगर रिज़र्व के मुख्य दरवाजे से चंद कदम दूर इस होटल में हर सुविधा मौजूद है जिसकी पर्यटकों को आवश्यकता रहती है, उम्मीद है विभाग की मेहनत और होटल मैनेजर विक्रम सिंह और उनकी टीम इस होटल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। यह संभावना आरटीडीसी की एमडी श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने क्षेत्र के अवलोकन उपरांत व्यक्त की।

छह माह पहले जिस प्रवर समिति को भेजा, उसे ही वापस लौटाया

मंत्री बोले- व्यक्तिगत मामलों में एनओसी की जरूरत नह

जयपुर। प्रदेश में भू-जल संकट से निपटने के लिए राजस्थान भूजल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक पर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींचखीं लिए। प्रवर समिति की अनुशंसा के साथ विधेयक को पास कराने के लिए बुधवार को सदन में पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे आमजन विरोधी, पानी पर पहरा बैठाने और लालफीताशाही बढ़ाने वाला बताते हुए सरकार को घेरा। इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी सुझाव दिए। इसके बाद भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बिल को फिर से प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान में यह पहला मौका है जब प्रवर समिति की सिफारिश पर तैयार विधेयक को वापस समिति को भेजना पड़ा। इस विधेयक को पिछले वर्ष 1 अगस्त को प्रवर समिति को भेजा था। इस विधेयक पर जिस प्रवर समिति में चर्चा हुई, उसमें पक्ष, विपक्ष, निर्दलीय सहित 17 सदस्य हैं। विपक्ष के रोहित बोहरा, राजेन्द्र पारीक, मनीष यादव, मनोज कुमार, थावरचंद शामिल है। समिति में चर्चा और अनुशंसा के बाद ही विधेयक सदन में पेश किया गया।

दो बार पहले भी प्रयास हुए विफल : भू-जल प्रबंधन के बारे में कानून लाने के प्रयास पहले दो बार विफल हो चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के कार्यकाल में करीब 28 साल पहले कैबिनेट में विधेयक पर विचार हुआ। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 2012 में विधेयक लाया गया, जो प्रवर समिति को भेजने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया। अब भू-जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए फिर विधेयक लाया गया है।

विपक्षी सदस्य बरसे और गरीब-जरूरतमंद लोगों पर भी एनओसी की बंदिश के जरिए लालफीताशाही में फंसाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा, नरेन्द्र बुढानिया ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि- 'मैं स्पष्ट कर दूं कि व्यक्तिगत मामलों में एनओसी की जरूरत नहीं होगी।' मंत्री ने विपक्ष के उस सुझाव को दोहराया, जिसमें मांग की गई कि प्राधिकरण की कमेटी का अध्यक्ष मंत्री या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो।

खंडार में जेजेएम कार्यों में अनियमितताओं का मामला उठा

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में खंडार विधानसभा में जेजेएम कार्यों में घोटाले का मुद्दा विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने उठाया। गोठवाल के मुद्दे पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ऐसे मामलों की जांच कराने का आश्वासन दिया। विधायक गोठवाल ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि 2023 के पहले ठेकेदारों के बिल पास कर दिए गए। एक राजनीतिक व्यक्ति के चलते यह बिल पास किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री नई पाइप लाइन स्वीकृत कर उसका काम शुरू कराएंगे। मंत्री ने जवाब दिया कि कई जगह से शिकायतें आ रही है। घटिया पाइपों को लेकर जो भी जांच होगी, वो कराई जाएगी। अगर दोबारा काम करना पड़ गया तो विभाग के स्तर पर दोबारा पाइपलाइन भी डालेंगे। पूरक सवाल में गोठवाल ने कहा कि क्या चौथ का बरवाड़ा के बाकी बचे गांव को भी योजना के तहत जोड़ा जाएगा। वहां 200 फीट पाइप डालना था, वहां सौ फीट ही पाइप डाला गया, क्या इस घोटाले की जांच कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि कुल 252 में से 192 में काम हो गया है और अन्य काम किए जा रहा है। यह काम जल्दी कर देंगे, जहां तक शिकायत की बात है सामने आई शिकायतों की जांच करा ली जाएगी।

कई ब्लॉक्स डार्क जोन में आ गए: शर्मा

विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने खुलेआम जल दोहन का अधिकार दे दिया था, इससे कई ब्लॉक्स डार्क जोन में आ गए। भूजल दोहन रोकने की दिशा में ये कानून सार्थक साबित होगा, लेकिन प्राधिकरण के अधिकार और जिम्मेदारी साफ तौर पर इसमें परिभाषित नहीं है। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि कानून में जिस क्षेत्र में दोहन प्रतिबंध किया गया है, उसका खुलासा नहीं है, कौनसा क्षेत्र होगा, जहां स्वीकृति की जरुरत नहीं होगी। विधायक रफीक खान ने कहा कि आप पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, घर में पानी दे नहीं पा रहे हो, इससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ने वाली हैं। बिना पानी के इंडस्ट्री कैसे लग सकेगी। इसमें केवल पानी के उपयोग पर सजा का प्रावधान किया गया है, जो उचित नहीं है। विधायक हाकम खान ने कहा कि ये प्राधिकरण भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। ट्यूबवैल की अनुमति में रिश्वत का खेल होगा। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि हर साल राजस्थान में एक मीटर से अधिक भूजल स्तर में गिरावट हो रही है। ऐसे में अतिदोहन को रोकने की दिशा में ये कानून जरुरी है। विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि आप तो एक कानून बना दो कि जो भी ड्रिलिंग मशीन वाला ट्यूबवैल खोदने जाएगा और बिना परमिशन खोदेगा तो उसको सजा होगी। सारे ठेकेदारों का संबंध पीएचईडी से है, तो कानून कैसे काम करेगा।

पानी पर झगड़ा

केंद्रीय मंत्री के दो भांजों में फायरिंग, एक की गई जान

भागलपुर। बिहार के भागलपुर के जगतपुर गांव में गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों के बीच हिंसक झड़प में एक भांजे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बताया जाता है कि नल से पानी भरने के विवाद को लेकर राय की चचेरी बहन के बेटों जयजीत यादव और विश्वजीत यादव के बीच गोलीबारी हुई। बीचबचाव में दोनों की मां भी घायल हो गई। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विश्वजीत ने दम तोड़ दिया। जयजीत की हालत गंभीर है। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

जेजेएम के काम के दौरान टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं होने का मुद्दा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका, हंगामा

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं देने को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। जल जीवन मिशन के काम के दौरान टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं होने के एक सवाल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बोलने की अनुमति नहीं दी। देवनानी ने कहा चार प्रश्नों पर नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं। इस पर विपक्ष उग्र हो गया। सब एक जगह एकत्रित होकर वैल की तरफ जाने लगे। सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हो गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। नाराज होकर विपक्ष ने प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के हाकम अली ने कहा कि फतेहपुर में जेजेएम का ठेका एक फर्म को दिया। उसने काम सबलेट कर दिया।

जिम्मेदार बताओ, जहां शिकायत दर्ज कराएं

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि काम करने वाले ठेकेदार को ही तीस दिन में सड़क की मरम्मत करनी होती है, लेकिन टेस्टिंग से पहले मरम्मत कर दें और कोई लीकेज हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए समय लग सकता है। इस पर हाकम अली ने कहा कि क्या छोटे-छोटे काम के लिए मंत्री को फोन करें? जिम्मेदार बताओ, जहां शिकायत दर्ज कराएं। एक साल से ज्यादा समय हो गया। सड़कें टूटी पड़ी है। मंत्री ने कहा कि एक्सईएन ऑफिस है, उसके ऊपर एसई ऑफिस है। चीफ इंजीनियर ऑफिस है। फिर भी कोई नहीं है तो मुझसे कहें। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए और कुछ बोलने लगे तो अध्यक्ष ने उन्हें टोक दिया। इससे सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया।

सदन में गूंजा जेजेएम घोटाला, पड़ोसी राज्यों से हक का पानी लेने की उठी मांग

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को जलदाय विभाग, जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जल जीवन मिशन में घोटाले की गूंज भी रही। साथ ही कई सदस्यों ने पड़ौसी राज्यों से राज्य का हक का पूरा पानी लेने में एकजुटता दिखाते हुए पूरा पानी लेने की मांग की।

हरियाणा हमें एक बूंद पानी नहीं देगा: बुढानिया

कांग्रेस विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया ने कहा कि शेखावाटी के जिलों को यमुना का पानी देने के लिए चुनाव से पहले कई बातें की गई, लेकिन सच ये है कि हरियाणा एक बूंद पानी की देने वाला नहीं है। केवल बाढ़ का पानी देने की बात है, जो वह तो अपने आप ही आ जाएगा। सर्दी के समय में भी गांवों में पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर माफिया इतने हावी है कि एक-एक हजार रुपाए में बेच रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर में गंदा पानी आ रहा है। इससे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। नहरी क्षेत्र में पानी के अभाव में फसलें बर्बाद हो रही है, पहले भी संकट आता रहा है, लेकिन पंजाब सीएम से बात करके उसका समाधान भी हुआ था। भाजपा केवल चुनाव में किसानों को बात करती हैं, बाद में भूल जाती हैं। पानी के नाम पर राजनीति की जा रही हैं। जेजेएम में घोटाला करने वालों को जेल भेजा, हम आपके साथ है।

20 साल में योजना पूरी नहीं, जनता के साथ धोखा: मीणा

कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने डिमांड पर बोलते हुए कहा कि 2005 की स्कीम 2025 में भी पूरी नहीं हुई। बार-बार विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद भी गंगापुर, सवाई माधोपुर और नादौती के लोगों के साथ धोखा हुआ हैं। ये योजना 2005 में शुरू हुई, एसपीएमएल कंपनी को ठेका दिया गया। 148 एमएलडी पानी का प्रोडक्शन करके गंगापुर, सवाईमाधोपुर और नादौती के क्षेत्र को पानी मिलना था, लेकिन आज तक योजना पूरी नहीं हुई है। पांचना बांध के ताले नहीं खुल रहे हैं। कमांड एरिया के किसान लगातार पानी की मांग कर रहे हैं।

मेरे घर तक भी पानी नहीं आया: रमीला

कांग्रेस की कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि जेजेएम में जलापूर्ति की बात हो रही है, लेकिन जनता को तो छोड़ो मेरे घर भी पानी नहीं आया है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान कार्य योजना बनाकर पानी देना चाहिए।

नागौर में ईआरसीपी का पानी मिले: लक्ष्मण राम

मेड़ता के भाजपा विधायक लक्ष्मण राम ने कहा कि बीती सरकार की नियत नहीं थी। मेरे क्षेत्र के लिए 1100 करोड़ जेजेएम में मंजूर हुए, लेकिन केवल 300 करोड़ ही खर्च हुए। पश्चिमी राजस्थान में 70 फीसदी जिले नहरी क्षेत्र से जुड़े हैं। नागौर में नहरें नहीं है। ईआरसीपी की योजना को यहां भी लाया जाए। पीने के पानी की भी व्यवस्था करें।

विधायक का पेपर खोया, बैठकर ढूंढने लगे हुसैन

पानी की डिमांड पर बोलते समय कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत का पेपर खो गया। इसे वे एक मिनट तक ढूंढते रहे। इसी दौरान वे बोलते-बोलते बीच में रुक गए, तो सदन में भी ठहाके लगने लगे।

शहीदों के बच्चे पानी के लिए सड़कों पर घूम रहे: श्रवण

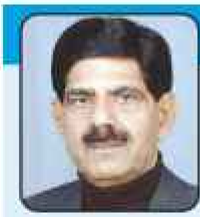

कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि जितने भी सीएम बने है, उन्होंने अपने अपने इलाकों का विकास करवाया। झुंझुनूं जिला पानी के अभाव में रहा। झुंझुनूं जिले के लिए तो शहीद होना ही लिखा है, देश के लिए अपने प्राण देने वाले शहीदों के बच्चे पानी के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। शर्म करो, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना तो विकास अधूरा रहा। जलदाय मंत्री को झुंझुनूं को पानी देना चाहिए। इस बार अगर मैं पानी नहीं पहुंचा पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने पानी के लिए वादा करके चुनाव लड़ा हैं। मुझे जनता ने 44 साल तक मैंडेट दिया है, क्या जवाब दूंगा, अगर पानी नहीं पिला सकता तो ऐसी राजनीति से क्या फायदा, हम कोई लकीर के फकीर है क्या..?

कांग्रेसराज में तीन नहरें हरियाणा को दी: सिंह

बीजेपी विधायक ने बहस के दौरान कहा कि कांग्रेस राज में लोहागढ़ हेड पर तीन नहर हरियाणा को दी, क्योंकि आपके मंत्री और चीफ इंजीनियर की जमीनें हरियाणा में थी। हमारा डेलिगेशन उस वक्त सीएम से मिला था और इस पर सवाल उठाए थे कि हमारा पानी हरियाणा को क्यों दिया। कांग्रेस ने राजस्थान में 50 साल राज किया, लेकिन जनता के साथ हमेशा धोखा हुआ। जेजेएम में भ्रष्टाचार हुआ। अब मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ाया गया है।

गुरवीर सिंह ने की सिंचाई और पेयजल के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा

चर्चा में भाग लेते हुए विधायक गुरवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय पर पानी के लिए प्रयास नहीं किए गये जबकि राज्य में भजनलाल सरकार के आते ही हरियाणा से पानी लाने पर काम किया गया। उन्होंने वर्षा जल संचयन की जरुरत बताते हुए कहा कि इस पर और काम करने की जरुरत हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जनआंदोलन के रुप में लेना चाहिए। विधायक अमित चाचाण ने अपने नोहर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने का मामला उठाते हुए कहा कि हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी दिलाया जाना चाहिए ताकि किसानों को पूरा पानी मिल सके। उन्होंने उनके क्षेत्र में किसानों की डिग्गियों के निर्माण के काम को भी पूरा कराये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज भी कई घरों तक पानी नहीं पहुंचा हैं ऐसे में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए।

(शेष अगले पृष्ठ पर...)

विधानसभा में विधायकों के बोल

जयपुर। भाजपा के विधायक बहादुर सिंह कोली ने कांग्रेस राज में जेजेएम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि भरतपुर में एक कांग्रेस विधायक थे। नाम नहीं लूंगा। उनके पास ठेकेदार आते थे तो वे कहते थे कि तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। कोई वर्ड में अपने आदमी को वे विधायक कहते थे कि बैग में 50 कुर्ते पायजामे हैं। मैं सड़क से जाऊंगा तू शॉर्टकट आ जा। एक चोर की जगह लोगों ने उनके आदमी को पकड़ लिया। बैग में देखा तो माल था। यह सत्य घटना है।

सोलर ट्यूबवैल लगे तो राहत मिलेगीः मील

भाजपा के खंडेला विधायक सुभाष मील ने कहा कि जल जीवन मिशन का समय 2028 करने पर पीएम नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हैं। हर घर में नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य समय नहीं बढ़ाते तो पूरा नहीं होता। इस साल बीस लाख घरों में जल कनेक्शन देने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने तय किया है। खंडेला में भूमिगत जल लगभग समाप्त हो चुका है। मांग है कि 22 करोड़ के जलापूर्ति कार्य की मंजूरी दी जाए। सोलर ट्यूबवैल लगे तो जनता को राहत मिलेगी। बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने का काम सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। बांधों के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

ईआरसीपी में केन्द्र से पैसे नहीं मिलेः पटेल

कांग्रेस के पीपल्दा विधायक चेतन पटेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में राजस्थान ही नहीं देशभर में धीमी गति से काम हो रहा है। मिशन में प्रदेश को जो बजट मिला था, उसका एक तिहाई ही सरकार खर्च कर पाई है। पानी प्रदूषित होने से कई बीमारियों से मौतें होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ईआरसीपी में 90 फीसदी केन्द्र की फंडिंग की बात कहीं गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। नवनेरा बांध कांग्रेस सरकार ने बनाया। सीएम तो केवल उसका निरीक्षण करने आए थे। यहां 70 हैक्टेयर जमीन पर पम्प हाउस बनाने जा रहे हैं, यह जमीन किसानों की है। सरकारी भूमि को अधिग्रहित कर इसे बनाएं।

जनता जल योजना संविदा कर्मियों को पूरा वेतन मिलेः पितलिया

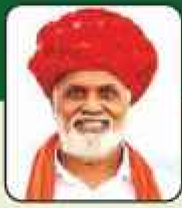

भाजपा के सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया में पानी की समस्या है। क्षेत्र जेजेएम योजना से वंचित है। स्वीकृतियां जल्द जारी होनी चाहिए, ताकि राहत मिल सके। 100 हैंडपंप और 50 ट्यूबवैल लगे तो जनता को जलापूर्ति में राहत मिलेगी। जलदाय विभाग में 70 हजार पद खाली हैं। तकनीकी पदों पर भर्ती की जाए, जो 20-25 साल से यहां संविदा पर काम कर रहे हैं, उन्हें वरीयता दी जाए। जनता जल योजना में कार्यरत कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया जाए। पूरा वेतन दिया जाए।

उम्मेद सागर को स्टोरेज को तैयार किया जाएः जोशी

भाजपा के सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी ने कहा कि अमृत दो योजना के सीवरेज कामों में जोधपुर में जमकर भ्रष्टाचार हुए। नए कार्यों के साथ पुरानी टूटी लाइनों को भी ठीक किया जाए। बावड़ियों सहित परम्परागत जल संरचनाओं को ट्यूबवैल से जोड़ा जाए, क्योंकि जोधपुर में निरंतर पानी नहीं निकालें तो यह जमीन से ऊपर आ जाता है। उम्मेद सागर को स्टोरेज को तैयार कर लिया जाए तो कायलाना पर निर्भरता घटेगी।

वर्तमान आबादी के हिसाब से पेजयजल आपूर्ति होः बरहड़

भोपालगढ़ विधायक गीता बरहड़ ने कहा कि की हालत यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रोजेक्ट बने हैं। वर्तमान हिसाब से पानी नहीं के बराबर है। पेयजल की आपूर्ति तीन घंटे ही होती है, आधे हिस्से में नहीं आता। कुछ जगह एक माह में भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जेजेएम में पंचायत स्तर पर टंकी निर्माण की जरूरत है। भारत अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहा है, सब जगह पानी सप्लाई होगा तो यह साकार होगा।

राज्य के हिस्से का शेष 0.60 एमएएफ पानी लेने का प्रयासः मंत्री रावत

पंजाब से नदियों का कम मिल रहा पानी, वो भी दूषित, फैल रही बीमारी

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान पंजाब से जुड़े पानी के मुद्दों की गूंज रही। एक सवाल रावी-व्यास नदी जल समझौते से जुड़ा था तो वहीं दूसरा सवाल पंजाब के लुधियाना से आ रहे गंदे पानी से जुड़ा था। विधायकों ने समझौते के अनुसार राजस्थान के हक का पूरा पानी दिलाने और गंदा पानी रुकवाने की मांग सदन में उठाई। भाजपा के कालीचरण सराफ ने रावी-व्यास नदी से पानी देने के लिए राजस्थान और पंजाब के बीच 1981 से जुड़े समझौते को लेकर सवाल किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जवाब में कहा कि रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल में से राज्य के हिस्से का शेष 0.60 एमएएफ पानी प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति भी की गई है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत राजस्थान को 8.60 एमएएफ पानी निर्धारित किया गया। वर्तमान में इसमें से 8 एमएएफ पानी राज्य को मिल रहा है।

किडनी-कैंसर के रोगी बढ़े

विधायक रुपिन्द्र सिंह कुन्नर के प्रश्न के जवाब में मंत्री सुरेश रावत ने स्वीकार किया कि पंजाब के लुधियाना शहर का प्रदूषित जल सतलुज नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसके अलावा जालंधर, नाकोदर तथा फगवाड़ा शहरों का सीवरेज जल एवं औद्योगिक अपशिष्ट काली बेन में प्रवाहित किए जाते हैं, जो कि सतलुज नदी में मिल जाता है। सतलुज नदी का पानी हरिके बैराज से इन्दिरा गांधी नहर, सरहिन्द फीडर व बीकानेर कैनाल के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है, जिसमें बीकानेर कैनाल का पानी गंग कैनाल में प्रवाहित होता है। इस दूषित जल की वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित 12 जिलों में कैंसर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं।

'हमारा पानी पाक जा रहा' : विधानसभा में बुधवार को जलदाय और जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान पाकिस्तान जा रहे पानी को रोक नहीं पाने, उससे पश्चिमी राजस्थान में पानी की कम आपूर्ति होने, जल जीवन मिशन घोटाले और गिरते भूजल स्तर से जुड़े मुद्दे छाए रहे। कांग्रेस के रुपिन्दर सिंह कुन्नर ने गंगानगर और हनुमानगढ़ में पानी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को राजस्थान की कैनाल की तरफ डायवर्ट कर लोगों तक पहुंचाया जाए।

ट्रांसफर के 2 माह बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे इंजीनियर्स

जबकि मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मांग चुके हैं जनवरी में ट्रांसफर के बावजूद रिलीव नहीं होने वाले अफसरों की सूची

जयपुर। जलदाय विभाग के इंजिनियर्स ट्रांसफर के 2 माह बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में सेवाएं दे रहे अभियंता तो अपने मूल 'जलदाय विभाग' को भी आँखे दिखाने से नहीं चूक रहे। इन कारनामों को देखते हुए स्वयं जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने उन अफसरों की सूची मांगी है, जिनका जनवरी माह में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन रिलीव होने के बजाय जो अफसर पुरानी कुर्सी से चिपके बैठे है। मंत्री की नाराजगी के बाद गत 4 मार्च को अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने भी आदेश जारी कर जनवरी माह के ट्रांसफर आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट अतिशीघ्र भेजने के लिए कहा था। ऐसे में सम्भावना है कि जलदाय विभाग ऐसे तमाम अफसरों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई कर सकता है।

सबसे ज्यादा हैरतअंगेज मामला तो राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड में सामने आया यहाँ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिशासी अभियंता रामनिवास सिंघल ने तो रिलीव होने के बजाय जलदाय विभाग के तबादला आदेश को ही ट्रिब्यूनल में चुनौती दे डाली। सिंघल की ओर से कहा गया कि' वह प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान आवासन मंडल में कार्यरत है, परन्तु जलदाय विभाग ने उनका तबादला आरयूआईडीपी में करने से पूर्व सहमति नहीं ली।' हालाँकि ट्रिब्यूनल ने साफ़ कहा है कि, जलदाय विभाग नए सिरे से सिंघल का स्थानांतरण आदेश जारी कर सकता है, इसमें कोई स्टे प्रभावी नहीं होगा। गौरतलब है कि गत 15 जनवरी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) प्रवीण कुमार लेखरा ने आदेश जारी कर 234 अधिकारियों का तबादला किया था, जिनमें अधिशासी अभियंता और सहायक अभियन्ता शामिल थे। इस आदेश के बावजूद करीब आधे इंजीनियर्स ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और जलदाय विभाग के ट्रांसफर आदेशों को ही मानने से इंकार कर दिया। इनमे राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिशासी अभियंता रामनिवास सिंघल और लखन सिंह मीणा भी शामिल थे। सिंघल को आरयूआईडीपी में तथा लखन सिंह मीणा को जल जीवन मिशन जयपुर में कार्यालय मुख्य अभियंता प्रथम के पद पर लगाया गया था, परंतु दोनों अफसर अभी भी यही कार्यरत है। हैरानी बात यह है कि इस तबादला आदेश को एक माह बीतने के बावजूद भी राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने दोनों अफसरों को रिलीव नहीं किया। इसी बीच अधिशासी अभियंता रामनिवास सिंघल ने जलदाय विभाग को आँखे दिखाते हुए तबादला आदेश के खिलाफ 'राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर' में अपील दायर कर दी। इसमें सिंघल की ओर से कहा गया कि, वह राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और जलदाय विभाग ने उनका तबादला आरयूआईडीपी में करने से पूर्व उनसे सहमति प्राप्त नहीं की, जो की गलत है। इस पर ट्रिब्यूनल अध्यक्ष विकास सीतारामजी भाले ने जनवरी माह के आदेश पर स्टे दे दिया, परन्तु उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जलदाय विभाग नियमानुसार नए सिरे से स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमे यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। उधर रामनिवास सिंघल ने जब राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनके साथी अभियंता लखन सिंह मीणा ने भी जलदाय विभाग के आदेश को मानने से इंकार कर दिया। इस पूरे प्रकरण के बीच राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा रहा। जबकि नियमानुसार जिस दिन तबादला आदेश जारी हुआ था, उसके अगले ही दिन इन दोनों अफसरों को रिलीव किया जाना था। परन्तु उच्चाधिकारियों की शह पर यह पूरा खेल होता रहा। कुछ ऐसा ही कारनामा जयपुर विकास प्राधिकरण में भी चल रहा है, जहां तबादला आदेश के 3-4 माह बाद भी इंजीनियर्स अब भी डटे हुए है, जबकि वहाँ भी नये इंजीनियर्स आ चुके है। हालांकि अब जलदाय मंत्री द्वारा संज्ञान लेने के बाद जनवरी माह के तबादला आदेशों की पालना नहीं करने वाले इंजीनियर्स पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

66 हजार से अधिक पानी के अवैध कनेक्शन पकड़े, नियमित हुए महज तीन हजार

अक्टूबर 2024 में शुरू हुए अभियान को नियमित चलाने के आदेश

जयपुर। जलदाय विभाग ने पांच माह में पानी के 66 हजार से अधिक अवैध कनेक्शन पकड़े, लेकिन इनमें से महज तीन हजार कनेक्शनों को ही नियमित किया जा सका, जबकि 61 हजार से अधिक कनेक्शनों का जल संबंध विच्छेद किया गया। अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए अवैध जल कनेक्शनों को हटाने एवं नियमित करने के लिए विशेष अभियान के दौरान 84.44 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल कर 33 एफआईआर दर्ज करवाई गई। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन से अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभागीय आदेश भी जारी किए गए हैं। अभियान के दौरान फील्ड के अभियंताओं की ओर से नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सघन कार्यवाही की जाएगी। राइजिंग मैन पाइप लाइन एवं वितरण लाइन से अवैध कनेक्शनों को हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

पानी की चोरी रोकने पर भी काम

मंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान नियमित रूप से पाइप लाइनों की पेट्रोलिंग कर अवैध कनेक्शनों को हटाने और जल राशि की चोरी को रोकने की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अवैध कनेक्शन करने एवं जल राशि की चोरी के कृत्य में संचालन एवं संधारण एजेंसी के कर्मचारी अथवा विभागीय कर्मचारी लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। नियमित एवं परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन वृत कार्यालयों की ओर से की जा रही कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा कर नियमित रिपोर्ट संबंधित मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करेंगे।

ईआरसीपी के बाद अब कदम वेस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट (डब्ल्यूआरसीपी) की तरफ

पश्चिमी राजस्थान में पानी की बढ़ी उम्मीद, गुजरात सीएम को लिखा पत्र

सकारात्मक संकेत, दोनों राज्यों में भाजपा सरकार और केन्द्र की मॉनिटरिंग भी बढ़ी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) से जुड़ा का विवाद खत्म होने बाद अब राज्य सरकार डब्ल्यूआरसीपी (पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना) का विवाद सुलझाने के लिए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें माही बेसिन का पानी केवल राजस्थान के उपयोग में लाने के लिए समझौते से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है। विवाद सुलझता है तो जालौर सहित प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की तस्वीर ही बदल जाएगी। वहीं, लाखों की आबादी को पेयजल भी उपलब्ध होगा।

उधर, जल संसाधन विभाग ने सर्वे तो करा लिया है, लेकिन दोनों राज यों के बीच जल समझौते पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने से बच रहे हैं। जलशक्ति मंत्रालय भी जल विवाद खत्म करने से जुड़े मामलों में मॉनिटरिंग कर रहा है।

इन जिलों को जोड़ा जा सकता है

पश्चिमी राजस्थान के जालौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा बांसवाडा, डूंगरपुर तक भी पानी पहुंच सकता है।

गुजरात से यह है समझौता

राजस्थान व गुजरात सरकार के मध्य 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ था। इसके तहत गुजरात सरकार से माही बांध निर्माण में 55 फीसदी लागत देने व 40 टीएमसी पानी लेने पर सहमति बनी। जब नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा, तब गुजरात राजस्थान के माही बांध का पानी उपयोग में नहीं लेगा और उस पानी का उपयोग राजस्थान में ही होगा। वर्षों पहले नर्मदा का पानी खेड़ा तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद समझौते की पालना नहीं हो रही है और गुजरात ने माही के पानी पर हक बरकरार रखा है। इस पानी को पहले 350 किमी लंबी कैनाल के जरिए जालोर तक लाने का प्लान है।

यह होगा फायदा

- 4.5 मिलियन हेक्टेयर रेगिस्तानी भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
- पश्चिमी राजस्थान की डेढ़ करोड़ से अधिक आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा।
- कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रुकेगा।
- भूजल स्तर में सुधार होगा।
- उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध होगा।

इसलिए उम्मीद ज्यादा

- गुजरात और राजस्थान दोनों जगह भाजपा की सरकार है। दोनों राज्यों के सीएम के बीच इस मामले में समन्वय हुआ है।
- केन्द्र सरकार लगातार अन्तरराज यीय पानी के इश्यू पर सक्रिय है। ईआरसीपी का विवाद ही उनके स्तर पर ही सुलझा है।
- पश्चिमी राजस्थान के कई विधायकों ने इसकी जरूरत जताई है। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक मुख्य हैं। हाल ही विधानसभा में भी इस मामले में सरकार पर दबाव बनाया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का जवाब भी सकारात्मक रहा।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पश्चिमी राजस्थान के विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं।

फिजिबिलिटी रिपोर्ट का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के सीएम से भी बात की है। उम्मीद है जल समाधान होगा और प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पानी के लिए काम होगा।

सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन मंत्री

पेयजल की गुणवत्ता आवश्यक

इक्कीसवीं सदी में भारत नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। अंतरिक्ष से लेकर सागर की गहराइयों तक भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सूचना क्रांति की बदौलत आज आम आदमी भी मोबाइल के जरिए कहीं भी संपर्क स्थापित कर सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी देश के करोड़ों लोगों कोस्वच्छ पानी तक पहुंच नहीं है। आजादी के करीब आठ दशक बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन जैसी सरकारी योजना भी बनी, लेकिन कई राज्यों में इस योजना पर ठीक तरह से अमल नहीं होने से अब तक लक्ष्य नहीं पाया जा सका है। इस योजना के तहत 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों तक नलों से जल पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया था, लेकिन राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल तो अब भी इस मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं। जल संसाधन से जुड़ी स्थाई समिति ने लोकसभा में इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। जल स्रोतों की कमी, भौगोलिक स्थिति, तकनीकी क्षमता-संसाधनों की कमी, कनेक्शन प्रक्रिया की जटिलता जैसे कारण भी लक्ष्य पूरा करने में बाधक माने गए हैं। सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार बड़े स्तर पर ऐसी योजना चला रही है तो संसाधनों की कमी तो आनी ही नहीं चाहिए। पेयजल आपूर्ति से जुड़ी किसी भी योजना पर किसी भी स्तर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए और कनेक्शन से जुड़ी जटिलताओं को तो तुरंत दूर किया ही जाना चाहिए। पानी हर प्राणी की बुनियादी आवश्यकता है। इसके बावजूद जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का मुद्दा हाशिए पर ही नजर आता है। सरकार भी घरों तक नल कनेक्शन पर ही ध्यान दे रही है। इस बात की परवाह नहीं की जा रही है कि नलों से घर तक स्वच्छ पानी पहुंच रहा है या नहीं। हो यही वजह है कि हाल ही पुणे और कुछ दूसरे शहरों में गिलियनबैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के मामले सामने आए। यह एक अस्थायी न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें तंत्रिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात हो सकता है। दूषित जल आपूर्ति के कारण लोगों की मौत के मामले भी सामने आते ही रहते हैं। खराब बुनियादी ढांचे, पानी को ठीक तरह से उपचारित नहीं करने और अनियंत्रित जल प्रदूषण के कारण ऐसे हादसे होते हैं। इसलिए जल जीवन मिशन महज नल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पानी की गुणवत्ता और पर्याप्त आपूर्ति पर भी ध्यान दिया जाए।

राजस्थान में पानी का संकट : गर्मी की दस्तक, तापमान भी बढ़ा, खर्च करने होंगे प्यास बुझाने के लिए 400 करोड़

10,000 गांव-ढाणी और 70 शहर प्यासे 691 बांधों में बचा 49 प्रतिशत पानी

जयपुर। राजस्थान में पीने के पानी की समस्या हर साल गर्मी के साथ विकराल रूप लेती है, लेकिन इस बार गर्मी जल्दी आ गई है, जिससे जल संकट और गहरा सकता है। दस हजार गांव-ढाणियों और 70 से अधिक शहरों में पानी की किल्लत के आसार है। जलदाय विभाग ने कंटीन्जेंसी प्लान के तहत पेयजल प्रभावित गांव-शहरों में आकस्मिक टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की है। करीब 400 करोड़ रुपए का इसके लिए फण्ड भी रिजर्व किया है। राज्य का क्षेत्रफल देश का 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। राज्य के 302 में से 203 ब्लॉक अत्यधिक दोहित, 23 विषम व 29 अर्द्ध विषम ब्लॉक है। हर साल गिरता भू-जल स्तर भी पेयजल समस्या को और अधिक बढ़ा रहा हैं। 2023 में राजस्थान में 16.74 बिलियन क्युबिक मीटर भूजल निकाला गया, जबकि केवल 11.54 बीसीएम पानी का पुनर्भरण किया गया। हालांकि 2024 में अच्छी बारिश के कारण कई जिलों में भूजल स्तर में सुधार भी हुआ हैं।

पेयजल संकट से निपटने क्या तैयारियां

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग के अधिकारियों की ओर से पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। इन प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही जिला और प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा ताकि पानी की समस्या की सूचना पर पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

भविष्य के लिए ये जरूरी

- जल संरक्षण के उपाय किए जाएं ताकि आने वाले समय में जल संकट को टाला जा सके।
- सरकार और आम जनता को मिलकर जल बचाने के प्रयास करने होंगे, तभी इस संकट से निपटा जा सकता है।

- जहां पर भूजल स्तर ऊपर होगा, उन पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में दो हजार 500 हैडपंप लगाए जाएंगे।
- प्रत्येक जिला कलक्टर को कंटीजेंसी के अन्तर्गत एक करोड़ का फण्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारू कर सकें।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए 70 करोड़ से नलकूप, टंकी, पाइपलाइन डालने का काम किया जाएगा।

सबसे ज्यादा प्रभावित जिले

पश्चिमी राजस्थान: बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर

दक्षिणी राजस्थान: डूंगरपुर, बांसवाड़ा

पूर्वी राजस्थान: करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर

उत्तर राजस्थान: सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर और जैसलमेर

प्रदेश के 691 बांधों में (फरवरी 2025) 49.14 फीसदी पानी उपलब्ध

संभाग	कुल क्षमता (मि.क्यू.मीटर में)	वर्तमान में पानी (मि.क्यू.मीटर में)	प्रतिशत
जयपुर (252)	2626.34	1439.38	50.54%
जोधपुर (117)	980.39	220.57	22.50%
कोटा (81)	4475.95	2658.75	59.40%
बांसवाड़ा (63)	2765.45	1426.99	51.60%
उदयपुर (178)	1850.69	604.01	32.64%
कुल (691)	12900.82	6339.70	49.14%

ग्राउंड वाटर की मौजूदा स्थिति (फरवरी 2025)

जिला	2023 में जलस्तर (मीटर)	2024 में जलस्तर (मीटर)	गिरावट प्रतिशत
जयपुर	50.2	52.7	5%
जोधपुर	65.8	69.3	5.3%
नागौर	85.5	90.1	5.4%
बाड़मेर	125.2	130.8	4.5%
सीकर	95.7	101.4	6%

जल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण

- अनियंत्रित बोरवेल खुदाई
- कम बारिश और सूखा
- पानी के किफायती इस्तेमाल की कमी

जल स्तर रोकने के लिए विशेषज्ञों की राय

- बोरवेल की खुदाई पर सख्त नियंत्रण जरूरी।
- बड़े पैमाने पर जल पुनर्भरण (रिचार्जिंग) तकनीकों को अपनाना होगा।

इसका क्या असर पड़ेगा...

- बीसलपुर से जयपुर, अजमेर और टोंक को होने वाली पानी की सप्लाई में कटौती हो सकती है।
- जवाई डैम से जोधपुर को पानी सप्लाई होती है, लेकिन यहां भी कमी की संभावना है।

जल संकट से निपटने के लिए ये जरूरी

- रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए
- हर गांव और शहर में बारिश के पानी को संचित करने की योजना बनाई जाए।
- बोरवेल पर सख्त नियंत्रण
- अनियंत्रित बोरवेल की खुदाई पर प्रतिबंध लगाकर सिर्फ लाइसेंसयुक्त बोरवेल को ही अनुमति दी जाए।
- नहरों और जल स्रोतों की सफाई और गहरीकरण नहरों और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए।

पानी सप्लाई की शहरों में स्थिति

- 117 शहरों में सप्लाई 24 घंटे के अंतराल में
- 111 शहरों में सप्लाई 48 घंटे के अंतराल में
- 12 शहरों में सप्लाई 72 घंटे के अंतराल में
- 11 शहरों में सप्लाई 96 घंटे से अधिक

60 फीसदी भूजल से आपूर्ति

पानी डिमांड की 60 फीसदी पूर्ति भूजल जल से हो रही है, शेष सतही जल परियोजनाओं से की जा रही है। प्रदेश में 85 शहर व कस्बे सतही जल स्रोत एवं 99 शहर भूजलीय जल स्रोत पर आधारित है। शेष 77 शहरी एवं भूजलीय दोनों जल स्रोतों पर निर्भर हैं। राज्य प्रमुख शहर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में सतही जल स्रोत से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जलदाय एवं भू-जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से बातचीत

सवाल: क्या राजस्थान में गर्मियों के दौरान पानी की पर्याप्त व्यवस्था है?

जवाब: गर्मियों के लिए पीने का पानी हर संभव उपलब्ध कराया जाएगा।

सवाल: कंटीजेंसी प्लान के तहत क्या व्यवस्था होगी?

जवाब: जिन गांव-शहरों में पानी की परेशानी होगी, वहां पर टैंकरों के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा।

सवाल: करोड़ों का हर साल बजट खर्च करने के बाद भी पेयजल संकट क्यों?

जवाब: पेयजल के लिए बड़ी योजनाएं बनी है, जिनका जनता को लाभ मिलेगा, इसमें समय लगता है।

सवाल: जेजेएम में घोटाला हुआ, अब क्या पटरी पर है?

जवाब: पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब हम पटरी पर ला रहे है।

सवाल: क्या गर्मियों में पेयजल व्यवस्था के लिए मुस्तैद है?

जवाब: हां, मैं खुद सभी जिलों का दौरा कर चुका हूं, अब गर्मियों में भी आकस्मिक दौरे करूंगा।

विशेषज्ञों की राय

- जलाशयों से पानी निकालने की स्थिति नियंत्रित होनी चाहिए।
- जलाशयों में जल संचयन को बढ़ाने के उपाय करने होंगे।

69 करोड़ का जगतपुरा फेज-11 व 82 करोड़ का डिग्गी रोड-प्रताप नगर प्रोजेक्ट पूरा, पानी सप्लाई 15 दिन में

80 हजार से ज्यादा की आबादी होगी लाभान्वित

जयपुर। जगतपुरा और डिग्गी रोड-प्रताप नगर क्षेत्र की 80 हजार से ज्यादा आबादी को जल्द खुशखबरी मिलेगी। 69 करोड़ रुपए की लागत वाला जगतपुरा फेज-।। व 82 करोड़ की लागत वाला सांगानेर क्षेत्र का डिग्गी रोड-प्रताप नगर प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है। इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी 7 टंकियों से 15 से 31 मार्च तक के अलगअलग शेड्यूल के तहत पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों के अनुसार होली के बाद जगतपुरा फेज-।। के तहत जल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

आज होगी बैठक

वहीं मुय अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल रविवार को गांधी नगर स्थित जलदाय कार्यालय में शहर की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसमें पेयजल किल्लत की स्थिति, डिमांड-सप्लाई की समीक्षा होगी।

हमारा फोकस गर्मी से पहले शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर है। जगतपुरा-सांगानेर में इसी महीने 7 टंकियों से पानी की सप्लाई शुरू करेंगे।

-मनीष बेनीवाल, मुय अभियंता शहरी, जलदाय विभाग

ये रहेगा पानी सप्लाई शुरू करने का शेड्यूल

- **15 मार्च** से जोतड़ावाला टंकी से सप्लाई शुरू होगी। आबादी लाभान्वित- 20 हजार
- **25 मार्च** से जगतपुरा फेज-।। की इन टंकियों से सप्लाई शुरू होगी

  बैंक कॉलोनी, बॉस एन्क्लेव, प्रेम सागर द्वितीय, जीरोता आबादी लाभान्वित- 42 हजार
- **30 मार्च** से जगतपुरा फेज-।। के तहत ही नंदन एन्क्लेव व रॉयल एन्क्लेव

  आबादी लाभान्वित- 22 हजार

जलदाय विभागः फील्ड विजिट नहीं... हीं जयपुर से तबादल

जयपुर। मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल ने गर्मी से पहले शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर रविवार को गांधी नगर कार्यालय में 7 घंटे तक जलदाय और बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों की क्लास ली। फील्ड विजिट के लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले इंजीनियरों को उन्होंनेन्हों दो टूक कहा कि सप्लाई मॉनिटरिंग में लापरवाह इंजीनियर का जयपुर के बाहर तबादला किया जाएगा। पृथ्वीराज नगर फेज प्रथम में आशीष विहार और गजसिंहपुरा टंकियां चालू होने पर भी कनेकशन जारी नहीं होने और वहीं प्रोजेक्ट विंग और जलदाय इंजीनियरों के बीच तालमेल नहीं होने पर सीई बेनीवाल बिफर गए। उन्होंनेन्हों कहा कि बीते तीन साल में शहर के कई इलाके बीसलपुर प्रोजेक्ट से जुड गए हैं इसके बाद भी टैंकरों की संया कम क्यों नहीं हुई है। बैठक में यह भी सामने आया कि कई अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी सप्लाई चैकिंग के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए। कुछ कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता ऐसे भी चिन्हित हुए जो एक बार भी फील्ड में सप्लाई चैक करने नहीं गए। अभियंता बेनीवाल ने सभी सहायक अभियंताओं को निर्देश दिए कि सब डिवीजन में 24 घंटे पेयजल सप्लाई के हिसाब से एक-एक डीपीआर के प्रस्ताव भेजे। बैठक में अतिरिक्त मुय अभियंता शुभांशु दीक्षित, उत्तर-दक्षिण सर्कल एसई व सभी फील्ड इंजीनियर मौजूद थे।

इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में शहर में बेहतर पेयजल प्रबंधन होना चाहिए इसके लिए सभी तैयारियां 31 मार्च से पहले कर ली जाएं। –मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहर

पृथ्वीराज नगर फेज-।।

पानी की टंकीः सप्लाई के दावों पर सवाल...एक साल में खड़े हुए सिर्फ पिलर

जयपुर। पृथ्वीराज नगर पेयजल प्रोजेक्ट फेज-।। का काम अगस्त तक पूरा कर मानसरोवर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा के लिए बीसलपुर सिस्टम से सप्लाई के प्रोजेक्ट इंजीनियरों के दावे और फर्म के काम की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। हाल ये है कि मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के भास्कर एन्क्लेव में दिसंबर 2023 में टंकी का निर्माण शुरू हुआ। 15 महीने बाद भी टंकी काम काम पिलर से आगे नहीं बढ़ा। जबकि इस क्षेत्र में सप्लाई के लिए वितरण तंत्र बिछ चुका है। टंकी के आस-पास की 10 कॉलोनियों के लिए बीसलपुर के पानी का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। उधर, टंकी निर्माण की कछुआ चाल के कारण फर्म के काम की भी पोल खुल रही है। क्योंकियों प्रोजेक्ट के अधिकारी फर्म के काम के हिसाब से ही अगस्त में सप्लाई शुरू करने की बात कह रहे थे। यहां नलकूपों से पानी सप्लाई होता है। लेकिन पानी इतना खारा है कि इसे पीने के काम में नहीं ले सकते। बाजार से पानी खरीद कर अपनी पेयजल जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अमन शर्मा, कैलाश सरोवर-पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र

भास्कर एन्क्लेव में टंकी का डोम बनना ही रह गया है। आगामी 10 दिन में फिर से काम शुरू होगा। - सुधीर वर्मा, अधीक्षण अभियंता, बीसलपुर प्रोजेक

माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन : जल संसाधन मंत्री

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के लिए पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य केंद्र सरकार के उपक्रम वेपकॉस द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राप्त संशोधित इन्सेप्शन रिपोर्ट का परीक्षण प्रक्रियाधीन है। जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए वेपकॉस को कार्यादेश दिया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से माही बेसिन के अधिशेष जल को कडाना बांध से सुजलाम-सुफलाम परियोजना के जरिये जालौर जिले को पानी उपलब्ध करवाने का अध्ययन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वेपकॉस द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। रावत ने कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत रन ऑफ़ वाटर ग्रिड स्थापित करने के एक घटक के रूप में माही बेसिन के अधिशेष जल को मार्ग में पड़ने वाले बांधों का पुनर्भरण करते हुए जवाई बांध में प्रवाहित कर जालौर जिले में पहुँचाया जाएगा। इसकी डीपीआर व पीएफआर भी वेपकॉस द्वारा बनाई जाएगी। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जल अधिशेष नदियों को कम पानी वाली नदियों से जोड़ने के लिए 30 लिंक्स का चिह्निकरण किया गया है। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक, शारदा-यमुना लिंक, यमुना-राजस्थान लिंक और राजस्थान साबरमती लिंक के लिए 3 अलग-अलग फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और नेपाल के साथ सहमति के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इससे पहले विधायक भैरा राम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ के जिलों में भी सिंचाई के लिए बनाई जा रही परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी उपादेयता के आधार पर डीपीआर बनाने हेतु बजट प्रावधान बाबत विचार किया जाना प्रस्तावित है।

50 हजार मीटर लोहे की पाइप लाइन घोटाला पीएचईडी ने पकड़ा

जोधपुर। जल जीवन मिशन में गांव-ढाणियों में हर घर जल पहुंचाने के 125 करोड़ के प्रोजेक्ट में जयपुर जोधपुर की ठेका फर्म ने जमकर फर्जीवाड़ा किया। इसमें गांवों-ढाणियों में 50 हजार मीटर लोहे की पाइप लाइन डालनी थी, जिसमें से 20% भी लाइन नहीं बिछाई। इसमें भी कुछ जगह लोहे की बजाय प्लास्टिक के पाइप डाले तो कुछ जगह पुरानी डाली गई लाइनों को अपनी बता ठेका फर्म ने करोड़ों का घोटाला किया। होली के पहले गठित हाई पॉवर जांच कमेटी अब पाली जिले में जवाई क्लस्टर-4 में ठेका फर्म के बिछाए पाइप लाइन की जांच में जुटी है। टीम को व्यापक घोटाले की जानकारी मिली है। इस टीम के साथ दैनिक भास्कर टीम ने भी जांच की। टीम ने पाली जिले के देसूरी व बाली के जेजेएमपी में शामिल 25 गांवों व ढाणियों में 400 किमी का सफर किया और ठेका फर्म के इन गांवों व ढाणियों में एलएंडटी की बिछाई लाइन के साथ-साथ 50 हजार मीटर लाइन बिछाने के दावे की जांच की। हर ग्राम पंचायत में जानकारी जुटाई तो ठेका फर्म का फर्जीवाड़ा चौड़े आ गया। इधर, जांच टीम की भनक लगते ही ठेका फर्म लोहे के पाइप लेकर रातोंरात टीम के चिह्नित गांवों में पहुंची और जेसीबी से खुदाई कर पाइप लाइन बिछाकर खुद के फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने का प्रयास किया। इस दौरान सड़क व पटरियां क्षतिग्रस्त हुई तो पीडब्ल्यूडी ने पीएचईडी अफसरों के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई तब मामला पकड़ में आया। ठेका फर्म ने देसूरी के सेली माता रोड भील बस्ती की टंकी (जीएलएसआर) से सेली माता मंदिर के रास्ते में तब तक 3 किमी लंबी लोहे की पाइप लाइन बिछा दी। बाद में पीएचईडी अफसरों ने काम बंद करवाया।

देसूरी में सेली माता रोड पर पाइप लाइन बिछाने का काम जीए इन्फ्रा ने किया। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जीए इन्फ्रा से पूछें, बाद में पाइप क्यों बिछाए

-पप्पूराम डारा, डारा कंस्ट्रक्शन

150 गांवों और 80 ढाणियों में लोहे की पाइपलाइन बिछाई नहीं

जयपुर की फर्म जीए इन्फ्रा व डारा (जॉइंट वेंचर फर्म) ने जेजेएमपी में जवाई क्लस्टर-4 के तहत 224 गांव और 123 ढाणियों में उच्च क्वालिटी के लोहे की पाइप लाइन बिछाने का सिंगल टेंडर लेकर दो साल पहले काम शुरू किया। 150 से ज्यादा गांवों और 80 से ज्यादा ढाणियों में पाइप लाइन बिछाने का दावा कर अफसरों की मिलीभगत से बिना पाइप लाइन बिछाए करोड़ों का भुगतान उठा लिया। ठेका फर्म ने ग्रामीणों के दबाव में जहां पाइप बिछाए वहां लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप बिछा दिए। 2021 में एलएंडटी व पंचायत की बिछाई पुरानी लाइनों को खुद की बिछाई बता दी। हैरानी की बात यह है कि पीएचईडी के तत्कालीन अफसरों ने बिना मौका निरीक्षण कर ठेका फर्म के काम का वेरिफिकेशन भी कर दिया। चार माह पूर्व मामले की शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में बड़े घोटाले की भनक लगी तो राज्य सरकार ने हाई पॉवर जांच कमेटी बनाई, जो 7 दिन से पाली में डेरा डाले बैठी है।

पीडब्ल्यूडी ने लाइन बिछाई तो आपत्ति की

पीडब्ल्यूडी जेईएन राजेंद्र कुमार ने बिना इजाजत सड़क व पटरियों की खुदाई करते देखा तो पूछताछ की, तब बताया कि जेजेएमपी में पाइप लाइन बिछा रहे हैं। पीएचईडी को पत्र लिखा, जवाब में कहा- योजना में न खुदाई का काम चल रहा और न ही 100 एमएम की पाइप लाइन बिछा रहे।

पीडब्ल्यूडी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र : पीएचईडी

पीएचईडी एईएन अशोक कुमार कुमावत ने 11 मार्च को पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर बताया कि पीएचईडी जेजेएमपी में ब्लॉक देसूरी सहित किसी भी ब्लॉक में खुदाई कर 100 एमएम डीआई पाइप लाइन बिछाने का कार्य नहीं कर रही है। पीडब्ल्यूडी कानूनी कार्यवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

महिलाओं ने फुलेरा जलदाय विभाग के सामने मटका फोट प्रदर्शन किया

फुलेरा। कस्बे में मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों की महिलाओं ने स्थानीय वार्ड पार्षदों के नेतृत्व में पेयजल आपूर्ति की अनियमितता को लेकर जलदाय विभाग के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इतना ही मुख्य मार्ग को भी जाम किया। जिसे स्थानीय पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर रास्ते को खुलवाया।

■ क्षेत्र का मुख्य रास्ता जाम किया, समझाइश के बाद खोला रास्ता

जलदाय विभाग के सामने मटका का प्रदर्शन करके महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा करीब 72 घंटो के अन्तराल में पेयजल सप्लाई की जाती है। जबकि बिल समय पर और पूरा लिया जाता है। वहीं आगे बताया कि क्षेत्र में जगह जगह पर पेयजल सप्लाई की लाईनें लीकेज पड़ी है। इस ओर प्रशासन का तनिक भी ध्यान नही है। वहीं मौके उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं जलदाय विभाग के एईएन के मध्य थानाधिकारी श्रवण कुमार ने वस्तु स्थिति को मध्य नजर रखते हुए उच्च अधिकारी से वार्ता कर समझाइश करते हुए आगामी तीन दिन बाद पेयजल समस्या का समाधान एवं जलदाय विभाग की अन्य समस्याओं से भी निजात दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पार्षदा आशा सैनी ने क्षेत्र में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता संजय शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पिछले 1 साल से अनियमित जलापूर्ति, पाईप लाईन लीकेज, खराब पड़े हेण्डपम्प, जलापूर्ति का अनिश्चित समय जैसी कई समस्याओं से अवगत कराते हुए उक्त समस्याओं से निजात दिलाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, महिला और पुरुष उपस्थित रहे।

छोड़नी होगी प्यास लगने पर कुआं खोदने की प्रवृत्ति

खराब हैण्डपप व बंद पड़े नलकूपों की सुध तब ही ली जाती है जब जलसंकट बढ़ने लगता है

हर बार गर्मी की शुरुआत से ही राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से जलसंकट की आहट शुरू हो जाती है। तापमान जिस गति से बढ़ता है उसी गति से यह संकट भी बढ़ता जाता है। इस बार भी गर्मियों के शुरुआती तेवरों के बीच ही जलसंकट का खतरा सामने आने लगा है। प्रदेश के जलाशयों में केवल 49.14त्न पानी बचा है, और 264 बांध पूरी तरह से सूख चुके हैं। यह स्थिति भयावह इसलिए भी है क्योंकिक्यों अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है। राज्य सरकार ने पेयजल संकट से निपटने के लिए 263 करोड़ रुपए की आपातकालीन योजना बनाई है, लेकिन यह योजना कितनी प्रभावी होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा केवल फाइलों में घूमता रहेगा या वास्तव में आम जनता को इसका लाभ मिल पाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भी कई इलाके आसन्न जल संकट का सामना कर सकते हैं। जगतपुरा और प्रताप नगर जैसी कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोग रोजाना संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। झुंझुनूं जिले में तो हालात और भी खराब हैं। यहां शहरी व ग्रामीण इलाकों में न केवल पानी की सप्लाई अनियमित है, बल्कि जो पानी आ भी रहा है, वह पीने योग्य नहीं है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है गांवों में पेयजल संकट को लेकर आए दिन धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को मजबूरी में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। समय रहते उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में जलसंकट का विकराल रूप होते देर नहीं लगने वाली। प्यास लगने पर कुआं खोदने की हमारे यहां पुरानी परिपाटी है। आम तौर पर खराब हैण्डपप व बंद पड़े नलकूपों की सुध तब ही ली जाती है जब जलसंकट को लेकर कोहराम मचना शुरू हो जाता है। गर्मी की शुरुआत में ही लोगों को धरना-प्रदर्शन कर पानी की मांग करनी पड़ जाए तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिमेदार लोग जलसंकट और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मामले में बेपरवाह हैं। पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को कागजों से बाहर निकालना होगा। जरूरत पेयजल संकट से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाने की है ताकि जलसंकट चरम पर नहीं पहुंचे। **– युगलेश शर्मा**

जेजेएम घोटाला: पीएचईडी के 3 एक्सईएन दो एईएन व एक जूनियर एकाउंटेंट सस्पेंड

जोधपुर। पाली जिले में जल जीवन मिशन के तहत जवाई क्लस्टर-4 में 224 गांव और 123 ढाणियों में पाइप लाइन बिछाने के 125 करोड़ के प्रोजेक्ट की जांच कर दी रिपोर्ट में हाई पॉवर कमेटी ने गंभीर अनियमितताएं पाईं। रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक विभाग ने पीएचईडी के 3 एक्सईएन, 2 एईएन व 1 जूनियर एकाउंटेंट को सस्पेंड कर दिया। ठेका फर्मों पर भी तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जेजेएमपी घोटाले की परतें उजागर की थी। कार्मिक विभाग ने आदेश निकालकर पीएचईडी पाली (परियोजना खंड प्रथम) के तत्कालीन एक्सईएन महेंद्र कुमार चेतीवाल (हाल में पीएचईडी, झुंझुनूं में), पीएचईडी पाली (परियोजना खंड-प्रथम) के तत्कालीन एक्सईएन महेंद्र कुमार वर्मा (हाल परियोजना खंड-झुंझुनूं), पीएचईडी पाली (परियोजना खंड-प्रथम) के तत्कालीन एक्सईएन रामलाल मीणा (हाल पीएचईडी कुचामन), पीएचईडी पाली (परियोजना खंड प्रथम) के तत्कालीन एईएन प्रतिभा कटारिया (हाल पीएचईडी जोधपुर), पीएचईडी पाली के तत्कालीन एईएन प्रेमराज मीणा (हाल पीएचईडी खंड मंडरायल करौली, पीएचईडी पाली (परियोजना खंड प्रथम) के तत्कालीन जूनियर एकाउंटेंट युधिष्ठिर सिंह (हाल कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, पाली) को से सस्पेंड कर दिया है।

एईएन व जेईएन पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

अलवर। विवेकानंद नगर क्षेत्र में रविवार सुबह सात बजे को जलापूर्ति का निरीक्षण करने पहुंचे सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। सहायक अभियंता सुनील कुमार यादव और कनिष्ठ अभियंता मोहित गुर्जर रविवार को जलापूर्ति करने निरीक्षण गए। पानी चालू करने के लिए यहां विवेकानंद नगर निवासी मोनू को चाबी दे रखी है। दोनों अधिकारियों ने युवक से गेटवाल की चाबी मांगी। मोनू ने चाबी देने से इनकार कर दिया और कार्मिकों को गाली-गलौज शुरू कर दी। इस बीच उसने जे जेब से चाकू निकाल कर सहायक अभियंता सुनील और कनिष्ठ अभियंता मोहित पर हमला कर दिया। दोनों कार्मिकों के हाथों में चोटें आई।

महारानी एलिजाबेथ ने शुरू की थी भांकरोटा की पानी की टंकी, अब गंदे पानी की हो रही सप्लाई व इनसेट में टंकी के ऊपर का ढक्कन भी नहीं है।

फर्जी भुगतान की पड़ताल कमेटियों ने किया तमाशा, रोकी जांच रिपोर्ट

जयपुर। जल जीवन मिशन (जेजेएम) में 55 करोड़ के फर्जी भुगतान की पड़ताल कर रही तीन कमेटियों ने फाइनल जांच रिपोर्ट रोक दी। इससे बिना पाइपलाइन डाले व अधूरी टंकियों के बदले ठेकेदारों को करोड़ों का पेमेंट करने वाले इंजीनियरों व लेखा विंग के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट देने का काम रुक गया है। फर्जी भुगतान के दायरे में करीब 150 इंजीनियर व अन्य अधिकारी है। पाइप लाइनों और बिना कार्यों के फर्जी भुगतान के मामले में जलदाय विभाग ने 15 एक्सईएन, 40 एईएन और 50 जेईएन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, अंकेक्षक को कारण बताओं नोटिस थमाए गए थे। लेकिन अब तक कमेटियों ने दोष ही तय नहीं किए है। वहीं पाली, डूंगरपुर, उदयपुर में भी फर्जीवाड़ा करने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है।

प्रदेश में 2000 करोड़ का फर्जी पेमेंट

जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, नीमकाथाना व कोटपूतली-बहरोड सर्किल में मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी व मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के कार्यों में अनियमित भुगतान का खुलासा हुआ है। कारण बताओ नोटिस के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को उलझाने के लिए जवाब में हजारों कागज थमा दिए। प्रदेश के दूसरे सर्किलों व डिविजनों में भी बिना पाइपलाइन डाले ही फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। पाली जिले में जेजेएम के तहत जवाई कलस्टर-4 में 224 गांव व 123 ढाणियों में ठेका फर्मों ने कई गांवों में पाइपलाइन ही नहीं बिछाई। चीफ इंजीनियर ने यहां लगे इंजीनियरों को सस्पेंड की सिफारिश की थी। यहां जॉइंट वेंचर में काम कर रही डारा कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य फर्म के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है।

विधानसभा में उठ चुका है फर्जीवाड़ा का मामला : जेजेएम में फर्जी पेमेंट व घटिया काम को लेकर कई विधायकों ने विधानसभा में मामले उठाए है, लेकिन इन मामलों में विभाग की ओर से अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। विभाग ने कई इंजीनियरों को सस्पेंड व एपीओ किया, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले आए। आरोपी इंजीनियर पूर्व की जगह ही काम कर रहे है। वहीं जेजेएम का टेंडर लेने वाली फर्मों पर भी ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई नहीं पाई है।

इन तीन कमेटियों को दी थी पड़ताल की जिम्मेदारी जांच

कमेटी-एकः कोटपूतली-बहरोड सर्किल में हुए फर्जी पेमेंट करने वाले इंजीनियरों के दोष तय करने के लिए अधीक्षण अभियंता केके अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कमेटी में एक्सईएन प्रेमराज सैनी व सहायक लेखाधिकारी एसडी गुप्ता को शामिल है। कमेटी- दोः जयपुर ग्रामीण और दौसा सर्किल के फर्जीवाड़े में लिप्त इंजीनियरों पर आरोप तय करने के लिए अधीक्षण अभियंता प्रदीप गुप्ता, एक्सईएन गंगाराम मौर्य, सहायक लेखाधिकारी दीपक तिवाड़ी रिपोर्ट देंगे। कमेटी तीनः अलवर और नीमकाथाना सर्किल में हुए फर्जी वाड़ा की जांच के लिए अधीक्षण अभियंता विश्वजीत नागर, एक्सईएन केके नारंग व सहायक लेखाधिकारी ओपी गाजू को कमेटी बनाई है।

सीएस की सख्ती : शहर में अभियान शुरू

फील्ड में उतरे इंजीनियर, 65 अवैध कनेक्शन काटे

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत के आदेशों के बाद जयपुर समेत पूरे प्रदेश में पेयजल लाइनों से अवैध कनेक्शन लेकर पानी खींचखीं ने वालों पर कार्रवाई के लिए अभियान ने रविवार से गति पकड़ी है। अभियान के दूसरे दिन जयपुर शहर में तैनात जलदाय इंजीनियर फील्ड में उतरे और अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उत्तर सर्कल एसई सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सर्कल के अलग-अलग डिवीजन में 35 कनेक्शन काटे गए जिनमें सर्वाधिक 23 अवैध कनेक्शन ब्रह्मपुरी डिवीजन में काटे गए। वहीं दक्षिण सर्कल एसई अनिल शर्मा ने बताया कि सर्कल में 30 अवैध कनेक्शन काटे गए। दक्षिण सर्कल में बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने जगतपुरा के बुद्ध विहार समेत अन्य क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन काटे। टारगेट-90 दिन अब अप्रेल से जून तक गर्मी का दौर चलेगा। इन 90 दिन में शहर की पेयजल व्यवस्था सुचारू रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में अब सभी फील्ड इंजीनियर टारगेट-90 दिन के हिसाब से ही 1 अप्रेल से पेयजल प्रबंधन पर काम करेंगे।

मुख्य सचिव के निर्देश पर जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में अवैध कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया है। क्योंकियों अवैध कनेक्शन सुचारू पेयजल व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। अवैध कनेक्शन काटने में कोताही बरतने वाले इंजीनियरों के खिलाफ सत कार्रवाई होगी। -मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता (शहरी), जलदाय विभाग

प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोगों को पेयजल से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी : जलदाय मंत्री

जिलों में पेयजल के आकस्मिक कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए की स्वीकृति

जयपुर। गर्मी के मौसम में प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोगों को पेयजल से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत कलेक्टर की अनुशंषा पर संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले जिलों में एक करोड़ रुपए तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्य करा सकेंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग विभागीय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए अधिकतम उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अधिकारियों को स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है जिससे गर्मी के मौसम में प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके। सभी जिलों में एक करोड़ रुपये की सीमा में ही खर्च की अनुमति होगी, अगर किसी स्थान इस सीमा के बाहर व्यय की आकस्मिक जरूरत होगी तो सक्षम स्तर से इस बारे में विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा।

अतिरिक्त वाहन व संविदा श्रमिकों की स्वीकृति

जलदाय मंत्री ने बताया कि गर्मी के सीजन में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए 110 नियमित वाहन के अलावा 01 मार्च से 31 मार्च 2025 के लिए 100 एवं आगामी 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक के लिए 400 अतिरिक्त वाहनों एवं आगामी 01 मई से 31 जुलाई तक 450 किराये के वाहनों के उपयोग की स्वीकृति जारी की है। स्वीकृत वाहनों का उपयोग हैंडपंप मरम्मत अभियान और समर कंटिंजेंसी कार्यों के साथ पेयजल परियोजनाओं तथा जलापूर्ति के कार्यों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। आगामी 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक के लिए 2 हजार संविदा श्रमिक व आगामी 01 मई से 31 जुलाई तक 2 हजार 500 संविदा श्रमिक सहित मार्च 2025 में भी 500 संविदा श्रमिकों की स्वीकृति जारी की गई है। 144 करोड़ रुपए से होंगे ग्रीष्मकालीन संवर्धन कार्य- जलदाय मंत्री ने बताया कि सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन संवर्धन कार्यों के तहत अति आवश्यक पेयजल व्यवस्था के लिए कुल 144 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है जिससे लगभग 1200 छोटे-छोटे कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है।

देर शाम तक टीमों की संख्या पांच से बढ़कर हो गई 13

एसीबी की गोपनीय जानकारी में एसई की 40 से अधिक सम्पत्ति मिली तो चलाया ऑपरेशन 40+

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में जब एसीबी टीमों ने गोपनीय जानकारी जुटाई तो 40 से अधिक सम्पत्ति ऐसी मिलीं, जिनको काली कमाई के जरिए इक्कट्ठा किया गया था। इसके लिए एसीबी ने अपना 'ऑपरेशन 40 प्लस' चलाया। एसीबी ने अविनाश के जयपुर स्थित 7 ठिकानों पर सर्च किया। यहां से उन्हें करीब 13 लाख रुपए नकद, 100 से अधिक सम्पत्तियों के दस्तावेज, 1.34 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फण्ड में निवेश के दस्तोवज मिले हैं। देर रात तक एसीबी की उनके आवास और ठिकानों पर सर्च कार्रवाई जारी थी। एसीची की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर सर्च जारी है। एसीबी डीजी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसई अविनाश शर्मा के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी मिली कि इसने 40 से अधिक सम्पत्ति अवैध तरीके से अर्जित की हैं। इसके लिए ऑपरेशन 40 प्लस चलाया। इसके लिए ही पूरी जानकारी जुटाई गई। सभी दस्तावेजों और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद करीब छह करोड़ 25 लाख 91 हजार 253 रुपए (253 प्रतिशत) की सम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित का मामला सामने आ गया।

इन्होंने किया सर्च

एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के सुपरविजन में एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानप्रकाश नवल अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर इझाबरमल एएसपी चौकी टोंक, सुरेन्द्र शर्मा एएसपी चौकी सवाईमाधोपुर, नवल किशोर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी दौसा, दीनदयाल पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी अजमेर, रघुवीर शरण शर्मा पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी एसआईयू जयपुर, छोटीलाल मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी चतुर्थ जयपुर की विभिन्न टीमों ने एक साथ मंगलवार अलसुबह आरोपी के जयपुर स्थित सात विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोन में पृथक से आरोपी की सम्पतियों का विवरण प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 6 टीमें लगाई गई।

यह सम्पत्तियां मिलीं

एसीबी कार्रवाई में आरोपी व इसके परिवाजनों के नाम जयपुर में 100 से अधिक सम्पत्तियों के दस्तावेज मिले। संदिग्ध अधिकारी के जयपुर स्थित आवास की तलाशी में करीब 13 लाख रुपए नकद, करीब 140 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 500 ग्राम चांदी के आभूषण मिले। संदिग्ध अधिकारी व परिवारजनों के कुल 7 बैंक खातों में करीब 30 लाख रुपाए मिले। संदिग्ध अधिकारी द्वारा म्यूचुअल फण्ड व शेयर मार्केट में करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश का हिसाब मिला। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चौपहिया व दुपहिया वाहनों को खरीदने व संचालन में करीब 25 लाख रुपए खर्च होना पाया। गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के बच्चों की शिक्षा संबंधित दस्तावेज, अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश, दो बैंक लॉकर भी मिले। बैंक लॉकरों की तलाशी लिया जाना शेष है।

जेडीए के एसई के ठिकानों पर एसीबी का छापा 6.25 करोड़ रु. से अधिक की मिली काली कमाई

नोट गिनने को मंगाई मशीन

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता अविनाश शर्मा व अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि शर्मा के पास गोपनीय सत्यापन में राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 6.25 करोड़ रुपए की आय से अधिक सम्पत्तियां अर्जित की। ये सम्पत्ति इनकी आय से करीब 253 प्रतिशत अधिक है। एसीबी टीम ने अविनाश शर्मा के जयपुर में गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र, जगतपुरा, प्रताप नगर एवं रिंग रोड के आस-पास 25 से अधिक कॉलोनियों में 100 से अधिक सम्पत्तियां खरीदने व निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होना सामने आया है। छापेमारी की कार्रवाई डीआईजी राहुल कोटोकी के सुपरविजन में हुई।

बिल्डरों को पहुंचाया लाभ

एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि मंगलवार को सुबह अविनाश शर्मा के यहां एसीबी की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इन पर काफी समय से निगरानी रखी जा रही थी। एक टीम को जेडीए, दूसरी को चाकसू नगरपालिका भेजा गया। एसीबी ने रुपए गिनने के लिए मशीन मंगवाई। खुलासा हुआ कि एसई ने भ्रष्टाचार करते हुए गृह निर्माण समितियों एवं बिल्डर्स को लाभ पहुंचाकर काफी कम दरों पर भूखण्ड अर्जित किए जिनकी खरीद के समय भी कुल कीमत करोड़ों रुपए थी।

स्कूली शिक्षा पर भी लाखों खर्च

जांच में सामने आया कि संदिग्ध अधिकारी अविनाश व परिवारजनों के 7 बैंक खातों में करीब 30 लाख रुपए होना सामने आया है। इनकी पुत्रियों की स्कूली शिक्षा, कोचिंग एवं उच्च शिक्षा मणिपाल यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में करीब 50 लाख रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ है। एसई ने म्यूचुअल फण्ड में करीब 90 लाख रुपए का निवेश किया है। इन्होंने चौपहिया व दुपहिया वाहनों को खरीदने व संचालन में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए थे।

इन ठिकानों पर किया सर्च

- मकान नम्बर 157 हिम्मत नगर गोपालपुरा मोड़ जयपुर
- कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जेडीए एवं जेडीए के विभिन्न जोन कार्यालय में
- प्लॉट नम्बर 10.21 कीर्ति सागर बदरवास जयपुर (श्री रघुराम ढाबा)
- प्लॉट नम्बर 58 इन्कम टैक्स कॉलोनी प्रथम जगतपुरा जयपुर
- किजस कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एमएस सैकर्ड कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय व नीलकण्ठ रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय 101 वास्तु श्री कॉलोनी मांगियावास जयपुर
- सी-371 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर
- प्लॉट नम्बर 75 राठी नगर बदरवास जयपुर

जेडीए से जुटाए जा रहे दस्तावेज

एसई अविनाश शर्मा ने अधिकतर सम्पत्ति 25 स्कीम व कॉलोनियों में अर्जित की है। शर्मा ने जेडीए में पदस्थापन के दौरान इन स्कीम व कॉलोनियों के नियमन एवं उनके विकास के क्रम में उक्त स्कीम व कॉलोनियों के डवलपर को नियमों के विपरीत फायदा पहुंचाया है। एसीबी ने जेडीए के अलग-अलग कार्यालय से से दस्तावेज जुटाए है।

वाणिज्यिक न्यायालय ने सुनाई सजा

एसीएस गुप्ता व सावंत को 3-3 माह का सिविल कारावास

जयपुर। शहर के वाणिज्यिक न्यायालय ने अवार्ड राशि का भुगतान नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता व भास्कर ए सावंत को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। सजा के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने प्रोजेक्ट पूरा करने वाली कंपनियों को भुगतान नहीं होने से संबंधित विवाद पर अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर यह आदेश दिए। नागौर मुकुंदगढ़ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष 2020-21 में सड़क का निर्माण में 167 करोड़

रुपए के बोनस भुगतान को लेकर वाणिज्यिक न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को राहत नहीं मिली। इसी मामले में भुगतान को लेकर विभाग के अतिरिक मुख्य सचिव गुप्ता का शपथ पत्र मांगा, जिसके नहीं मिलने पर उन्हें तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। उधर, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पाइपलाइन डालने के प्रोजेक्ट में करीब 31 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने के मामले में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आर्बिट्रेटर की ओर से एल एंड टी कंपनी के पक्ष में करीब 31 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया। इसकी पालना का मामला वाणिज्यिक न्यायालय पहुंचा, जहां बार-बार अवसर देने के बावजूद भुगतान के संबंध में सावंत का शपथ पत्र पेश नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने सिविल कारावास का आदेश दिया।

अमेरिकी नीतियां, भू-राजनीतिक तनाव 2025 में वैश्विक व्यापार के लिए जोखिम : अंकटाड

वैश्विक व्यापार 1.2 लाख करोड़ बढ़कर 33 लाख करोड़ डॉलर

सेवा व्यापार में 9% की वृद्धि और माल व्यापार में 2% की वृद्धि

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक गतिविधि के चालू वर्ष में धीमी गति बनाए रखने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीतियों में बदलाव, वैश्विक व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक चुनौतियों जैसे कारकों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है जिसका व्यापार वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (अंकटाड) ने अपने नवीनतम वैश्विक व्यापार अपडेट में यह बात कही है। इसके अलावा उसने कहा है कि व्यापार नीति में वृद्धि की संभावना 2025 के लिए वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण पर अनिश्चितता की छाया डालती है।

चीन का वृद्धि लक्ष्य 5 प्रतिशत

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक मुद्रास्फीति में अपेक्षित कमी और 2025 के लिए चीन के आर्थिक प्रोत्साहन - लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि लक्ष्य के साथ - वैश्विक व्यापार को कुछ बढ़ावा दे सकते हैं। वैश्विक व्यापार अपडेट ने संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कार्यान्वयन में बढ़ती प्रवृत्ति का उल्लेख किया है जिसमें व्यापार उपायों को गैर-व्यापार नीति उद्देश्यों से जोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति है।

टैरिफ का प्रभाव पड़ेगा

इसमें कहा गया है कि यह बदलाव विशिष्ट देशों को लक्षित करने वाले व्यापक नए टैरिफ के कार्यान्वयन में स्पष्ट है, साथ ही स्टील और एल्युमीनियम जैसे विशेष उत्पादों को प्रभावित करने वाले अधिक लक्षित टैरिफ भी हैं। इन टैरिफ का वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

शंघाई कंटेनराइज्ड फ्रेट में कमी

रिपोर्ट ने कहा गया है कि 2025 के पहले महीनों में कंटेनर शिपिंग की मांग में उल्लेखनीय कमी आई है, जैसा कि शंघाई कंटेनराइज्ड फ्रेट इंडेक्स में उल्लेखनीय कमी से पता चलता है। इसमें कहा गया है "एससीएफआई में गिरावट कमजोर व्यापार मात्रा की ओर इशारा करती है, जो वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मंदी का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो कोयला, लौह अयस्क और अनाज जैसी थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग दरों को ट्रैक करता है, 2024 की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्तर पर बना हुआ है।"

माल और सेवा व्यापार बढ़ा

अंकटाड के अनुसार, 2024 में वैश्विक व्यापार में लगभग 1.2 लाख करोड़ डॉलर का विस्तार हुआ और यह 33 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इससे सेवा व्यापार में 9 प्रतिशत की वृद्धि और माल व्यापार में 2 प्रतिशत की वृद्धि का परिणाम है। जबकि विकासशील देशों, विशेष रूप से चीन और भारत ने 2024 के दौरान औसत से बेहतर व्यापार विस्तार देखा, कई विकसित देशों में व्यापार सुस्त रहा।

अंततः तीसरे पक्ष भी शामिल

रिपोर्ट में कहा गया है कि एकतरफा और अत्यधिक प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां तीव्र प्रभाव पैदा कर सकती हैं, और ऐसे उपाय अक्सर प्रभावित व्यापारिक भागीदारों से जवाबी कार्रवाई को प्रेरित करते हैं, जिससे अक्सर व्यापार बाधाओं का एक चक्र बनता है जिसमें अंततः तीसरे पक्ष भी शामिल हो सकते हैं।

हमारी ज़िन्दगी
Political Magazine and Newspaper
निष्पक्ष, निर्भीक, हर खबर की तह तक

भारतीय NEWS
www.bhartianews.in

द्वारा प्रकाशित

राजस्थान जनप्रतिनिधि ग्रन्थ

16वीं विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायकों तथा 18वीं लोकसभा के प्रदेश के सभी 25 सांसदों के सचित्र जीवन परिचय, चुनाव विश्लेषण व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण ग्रन्थ

निदेशक : मंजू आर्य

अपनी प्रति आज ही बुक करें

मूल्य 400/- रुपए

9314028732 राकेश प्रसून | 8560990000 सौरभ माथुर

/BhartiaNews /hamarizindagimagazine/ /BhartiaNews.in

हमारी ज़िन्दगी

Political Magazine and Newspaper

राजस्थान में गत 24 वर्षों से जन-जन तक पहुंच रही है

• जलदाय • पीडब्ल्यूडी • जेडीए • नगर निगम • सिंचाई • आरएसआरडीसी • राजनीतिक मंच की जानकारियों से परिपूर्ण मासिक पत्रिका

आज ही घर/ऑफिस में मंगाने के लिए कन्फर्म करें।

9314028732 राकेश प्रसून | 8560990000 सौरभ माथुर

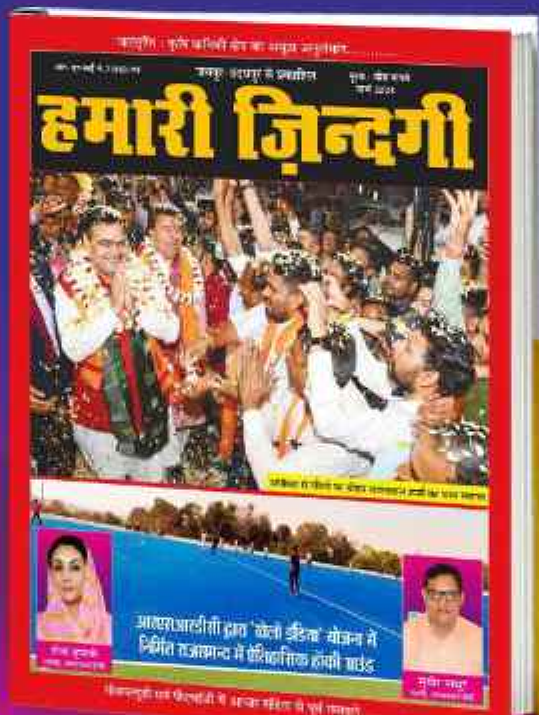

/BhartiaNews /hamarizindagimagazine/ /BhartiaNews.com

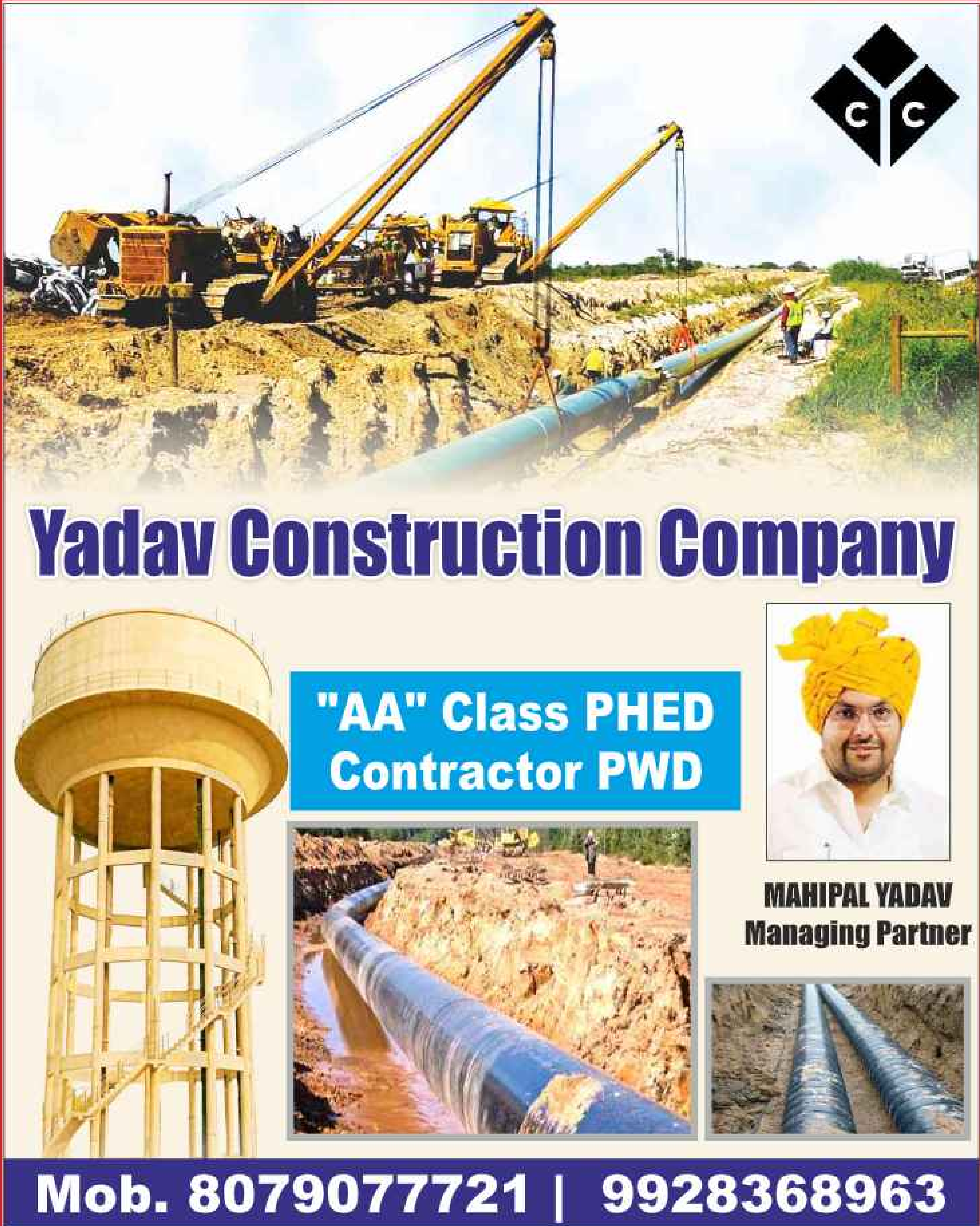
CYC
Yadav Construction Company
"AA" Class PHED
Contractor PWD
MAHIPAL YADAV
Managing Partner
Mob. 8079077721 | 9928368963